RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

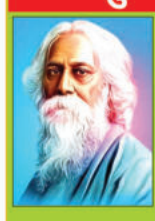

प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है।
रविन्द्रनाथ टैगोर

वर्ष-08, अंक - 02 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 09 अक्टूबर 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

जब दवा ही दर्द का सबब बन जाए...!

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

पिछले दिनों घटित दो घटनाओं ने देश का ध्यान आकर्षित किया है। पहली घटना है कि, कोल्डड्रिंक कफ सिरप देने के बाद कई बच्चे कालकलंवित हो गए। वे मासूम बच्चे जिनमे अभी अच्छे और बुरे की समझ भी विकसित नहीं हो पाई थी और सर्दी-खांसी के लक्षण होने पर उनके परिजन उन्हें दवाखाने ले गए थे और डॉक्टर ने उन्हें दवाई के रूप में कफ सिरप, कोल्डड्रिंक सिरप दिया था। उन्हें क्या पता था कि, जो उन्हें दवाई के रूप में दिया जा रहा है वह वास्तव में जहर है। एक साथ इतनी संख्या में हुई मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली और तत्काल जांच के नाम कार्यवाही प्रारंभ की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई। जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि, जब तक कोई घटना घटित न हो सब कुछ सही रहता है। वही कोई भी घटना सामने आने के बाद खामियों पर नजर सरकार की पड़ती है। मतलब साफ है कि, कहीं न कहीं सिस्टम में ही गंभीर अनियमिताए है जो देर सवेरे ऐसी घटनाओं के बाद आमजन के सामने आ पाती है। जिसके बाद प्रशासन की कुंभकरणी नींद खुलती है, तत्काल जांच बिठाई जाती है, कुछ कार्रवाई की जाती है और मामला कुछ पुराना होने के बाद लोग भूल जाते हैं। और फिर से सामान्य कामकाज चालू हो जाता है जब तक की कोई नई घटना सामने न आ पाए।

यह ट्रेंड पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। गत वर्षो में मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से कई मजदूरो की जान चली गई थी जिसके बाद पूरे मध्यप्रदेश में पटाखा व्यवसाययों की जांच की गई थी। ठीक उसी प्रकार कफ सिरप के बाद भी प्रदेश में दवाइयो की गहन जांच की जा रही है। ऐसे में आम आदमी के मन में प्रश्न उठ रहा है कि, शासन और प्रशासन ने जो नियम कायदे बनाये है उनका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए और अगर नियम कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है तो शासन द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। तथा निरीक्षण सतत चलने वाली प्रक्रिया होना चाहिए न कि किसी भी घटना के घटित होने के बाद। और अगर कोई घटना घटित हो रही है तो इसका सीधा कारण है कि, नियमों का पालन नहीं किया गया है और निरीक्षण भी समय-समय पर नहीं किया गया है। ऐसे में किसी भी घटना के घटित होने के बाद जितना कसूर संबंधित का रहता है, उतना ही कसूर निरीक्षण कर्ता अधिकारी का भी रहता है। ऐसे में दोनों पर ही समान कार्रवाई की जाना चाहिए।

39 गंभीर और 325 बड़ी खामियां

तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन कंपनी में मध्यप्रदेश के विशेष जांच दल ने जांच की तो कई गंभीर अनियमिताये पाई गई। जिसमें कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं था। फर्म ने विश्लेषणात्मक परीक्षण विधियो का सत्यापन नहीं कराया था, विलिजेंस सिस्टम नहीं पाया गया जिसमें दवाओं के दुष्प्रभाव का आकलन किया जाता है।

क्वालिटी इंश्योरेंस विभाग कंपनी में नहीं था। यही नहीं किसी बेच को रिलीज करने के पहले किसी अधिकारी को नोडल नहीं बनाया गया था। गुणवत्ता जांच में सिरप के सैंपल खुले में लिए जाते थे। कफ सिरप सहित अन्य उत्पाद कॉरिडोर में खुले में रखे हुए थे जहां पर्याप्त सफाई नहीं थी।

जिसके बाद आम आदमी का कहना है कि, इंसानो हेतु दवाई बनाने वाली कंपनी के ये हाल है तो अन्य कंपनियों में निर्धारित मानको को क्या पूरा किया जाता होगा सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है...?

दूसरी घटना भी न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट की थी जिसमें एक वकील ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) पर जूता फेंकने का प्रयास उस वक्त किया जब वे न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे। यह मामला किसी छोटी-मोटी अदालत का नहीं देश के सुप्रीम कोर्ट का था। जिसके बाद आम चर्चा का विषय है कि, सभी को न्याय दिलाने वाले वकील ही जब कानून को अपने हाथ में लेने लग जाए तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि, देश किस दौर से गुजर रहा। असहमति का तात्पर्य यह नहीं है कि, आप कानून को हाथ में ले ले। भारतीय लोकतंत्र में विरोध के लिए भी कुछ तरीके हैं बार और बेच न्याय व्यवस्था के दो स्तंभ है दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं जो भी बार या बेच इस पवित्र संस्था को कमजोर करने की कोशिश करता है तो वह सिर्फ इस संस्था को नहीं बल्कि देश की न्यायिक व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है।

संविधान पर प्रहारः मुख्य न्यायाधीश के परिवार की कड़ी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंके जाने की घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना पर मुख्य न्यायाधीश की बहन कीर्ति गवई ने कहा कि, यह हमला केवल उनके भाई पर नहीं, बल्कि भारत के संविधान पर हमला है।

अपने संदेश में कीर्ति गवई ने कहा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और इसकी गरिमा बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो हमला हुआ, वह किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर है जो हमें अधिकार और समानता देती है।

उन्होंने जनता से अपील की कि वह संविधान की रक्षा के लिए सजग रहें और किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में न लें। कीर्ति गवई ने कहा कि हम जो भी आवाज उठाएं या कार्य करें, वह संविधान के ढांचे के भीतर हो, जैसा बाबा साहेब अंबेडकर ने सिखाया है। मुख्य न्यायाधीश गवई की मां ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह न सिर्फ न्यायपालिका पर, बल्कि पूरे राष्ट्र पर कलंक लगाने वाली हरकत है। कुछ लोग असहमति को अभद्रता में बदल रहे हैं, जो समाज के लिए खतरनाक है।

गौरतलब है कि सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में राकेश किशोर नामक एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल उन्हें कोर्ट से बाहर कर दिया। बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाते हुए राकेश किशोर का वकालत लाइसेंस रद्द कर दिया।

ब्रिटेन के पीएम दो दिवसीय भारत यात्रा पर

मुंबई।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर गुरुवार को दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। हवाईअड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टार्मर की यह पहली भारत यात्रा है। उनका यह दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेता विजन 2035 रोडमैप के तहत व्यापार, रक्षा, नवाचार, शिक्षा और जलवायु जैसे क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। स्टार्मर के साथ ब्रिटेन के उद्योगपतियों, विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों और मंत्रियों का एक उच्चस्तरीय दल भी आया है। संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी और स्टार्मर मुंबई में होने वाले ÷वैश्विक फिनटेक उत्सव÷ में शामिल होंगे। यह यात्रा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुई प्रगति को आगे बढ़ाने का अवसर मानी जा रही है।

पहले दुआ, फिर सलाम : आज़म और अखिलेश की मुलाकात

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार नए उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अब तक समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से नाराज़ चल रहे मुलायम सिंह यादव के करीबी वरिष्ठ सपा नेता आज़म ख़ान बुधवार को उनसे मिले।

जिस मुलाकात का इंतज़ार यूपी की सियासत में लंबे समय से किया जा रहा था, वह आखिरकार बुधवार को हो गई। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे कृ मकसद था आज़म ख़ान से मुलाकात करना। इस मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी सामने आ चुकी हैं। आज़म के घर पहुंचते ही अखिलेश ने सबसे पहले हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों को नमस्कार किया। तभी पीछे से आज़म ख़ान आए और दोनों के बीच वह बहुचर्चित तस्वीर सामने आई जिस पर सबकी नज़र थी। यह मुलाकात तय समय से अधिक, करीब 1 घंटा 40 मिनट तक चली।

सपा के उच्च स्तर के सूत्रों के अनुसार, इस लंबी बातचीत का उद्देश्य आज़म ख़ान की नाराज़गी दूर करना था। यूपी की राजनीति में आज़म आज भी एक अहम चेहरा बने हुए हैं। कभी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी रहे आज़म से मिलने उनके बेटे अखिलेश खुद आए थे।

मुलाकात के दौरान माहौल भी खुशनुमा रहा। हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करने के बाद अखिलेश ने आज़म के आने का इंतज़ार किया। जैसे ही आज़म पहुंचे, उन्होंने वहां खड़े लोगों को कुछ इशारा किया। अखिलेश ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा किसे बुला रहे हैं? और फिर आज़म के पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। दोनों साथ-साथ अंदर चले गए।

बाहर मौजूद पत्रकारों को देखकर अखिलेश मुस्कुराए और हाथ हिलाकर संकेत दिया कि हम अब भी साथ हैं।

बताया जा रहा है कि इस मुलाकात की योजना पहले एक घंटे की थी, लेकिन चर्चा लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक चली।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी हवा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा।

फरार 4 आतंकियों की तलाश में जुटा सुरक्षाबल

जम्मू एजेंसी।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार देर रात आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर चार आतंकी जंगल की ओर भाग निकले। इसके बाद से ही सुरक्षाबलों ने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

बीरंथुब क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं। आतंकियों के भाग जाने के बाद पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की संयुक्त टीमें पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही हैं। बुधवार सुबह तक यह अभियान जारी है। सुरक्षाबलों को आशंका है कि चार आतंकी अब भी आसपास के जंगलों में छिपे हो सकते हैं। राजौरी-कोटरणका-बुधाले मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों की गहन जांच की जा रही है। इसी बीच, आतंकवादी फंडिंग मामले में राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने आज सुबह श्रीनगर, गांदरबल, वडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और गांदरबल में छापेमारी की है।

इससे पहले सितंबर माह में कुलगाम जिले के गुड्डर जंगलों में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस ऑपरेशन को ÷ऑपरेशन गुड्डर÷ नाम दिया गया था। इस मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए थे, जबकि दो जवान शहीद हो गए थे। मारे गए एक आतंकी की पहचान शोपियां निवासी आमिर अहमद डार के रूप में हुई थी, जो लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़ा था और सितंबर 2023 से सक्रिय था।

यह आतंकी उन 14 आतंकवादियों की सूची में शामिल था, जिन्हें पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित किया था। सुरक्षाबल अब राजौरी क्षेत्र में भी इसी तरह की सतर्कता बरतते हुए आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं।

हमलाः 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 19 आतंकी भी ढेर

इस्लामाबाद एंजेसी।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के हमले में मंगलवार रात 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इनमें 2 अधिकारी और 9 जवान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, अफगानिस्तान सीमा के नजदीक पाकिस्तानी सेना टीटीपी के खिलाफ अभियान चला रही थी। इस दौरान दोनों ओर से मुठभेड़ हो गई, जिसमें टीटीपी के 19 आतंकियों को भी मार गिराया गया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (आईएसपीआर) ने आरोप लगाया कि हमलावरों को भारत से समर्थन मिल रहा है। सेना का कहना है कि वह इन आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। पिछले कुछ महीनों में टीटीपी ने पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सैनिक कुर्रम जिले में अभियान के लिए पहुंचे थे। तभी आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर गोलाबारी शुरू कर दी। बाद में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि उनके लड़ाकों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि, उन्हें कुर्रम में भारतीय प्रॉक्सी संगठन फितना अल-ख्वारिज से जुड़े आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया। पाकिस्तानी सेना टीटीपी को फितना अल-ख्वारिज कहती है। अरबी भाषा में फितना का अर्थ ÷उपद्रवी÷ और अल-ख्वारिज का अर्थ ÷चरमपंथ के रास्ते पर चलने वाले लोग÷ होता है।

2007 में बेतुल्लाह मेहसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की स्थापना की थी। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के विरोधी गुटों के लोग शामिल थे। इनकी लड़ाई पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ है। इस संगठन के कई समर्थक पाकिस्तानी सेना में भी मौजूद हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि टीटीपी परमाणु हथियारों तक पहुंच सकता है।

इससे पहले, पाकिस्तानी वायुसेना ने 21 सितंबर की रात करीब 2 बजे अपने ही नागरिकों पर चीन निर्मित जे-17 लड़ाकू विमानों से आठ लेजर-निर्देशित बम गिराए थे। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी के एक गांव में किया गया था।

सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक है भारतीय वायुसेना- वायुसेना प्रमुख

गाजियाबाद, एजेंसी।

भारतीय वायुसेना ने बुधवार को अपना 93वां स्थापना दिवस मनाते हुए वायुसेना के जांबाज लड़ाकू पायलटों एवं अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया।

गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना अड्डे पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने परेड की सलामी ली और वायुवीरों को संबोधित किया।

इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंधु' के दौरान भारतीय वायुसेना ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त, वायुसेना ने अन्य देशों में आए अंतरराष्ट्रीय संकटों में भी सक्रिय योगदान दिया। राहत सामग्री और कर्मियों को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया। जिस तेजी, सजगता, करुणा और विश्वसनीयता के साथ भारतीय वायुसेना ने कठिन परिस्थितियों में आशा की किरण जगाई, वह सेवा के क्षेत्र में सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक है।

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि, यह अभियान हमारी सामरिक दक्षता, अनुशासन और निष्ठा का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सावधानीपूर्वक योजना, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प के बल पर हमारी वायुसेना ने असंभव को संभव कर दिखाया। स्वदेशी हथियारों और तकनीक के इस्तेमाल से भारत की वायु शक्ति और अधिक मजबूत हुई है। हमारे स्वदेशी विमानों और मिसाइलों ने दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक सटीक और विनाशकारी प्रहार किए हैं।

इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम 'सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर' रखी गई है। यह दिवस 'ऑपरेशन सिंधु' के वीर योद्धाओं को समर्पित किया गया। समारोह में 97 वायुवीरों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, ÷हमें गर्व है कि भारतीय वायुसेना आज दुनिया की सबसे सक्षम वायु सेनाओं में से एक है। हमारी सबसे बड़ी सफलता नई प्रणालियों, हथियारों और तकनीक के तेजी से एकीकरण में रही है।

कलेक्टर्स स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाएं और करें निरीक्षण- सीएम

माही की गूंज, झाबुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक नई सुविधाए प्रारंभ की गई हैं। कलेक्टर्स स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करें और हॉस्पिटल में सतत् निरीक्षण करें। जिससे हॉस्पिटल की कमियों को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि, आयुष्मान कार्ड धारकों को पूरा लाभ दिलाएं और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच को आसान बनाया जाये। जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर भी अनेक कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। वर्तमान में तीस से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं शीघ्र इनकी संख्या 50 हो जाएगी। प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले के नागरिकों को मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रचलन में है, उसे अंतिम रूप देकर भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण किया जा रहा है।? मुख्यमंत्री डॉ. यादव कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिन द्वितीय सत्र 'स्वास्थ्य एवं पोषण' को संबोधित कर रहे थे।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव ने राज्य में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुदृढ़ करने कलेक्टर्स के साथ विस्तृत चर्चा की। सत्र में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग (एनसीडी), क्षय उन्मूलन और सिकल सेल उन्मूलन के लिए ठोस रणनीति पर विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री यादव ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दिशा में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की नियमित हीमोग्लोबिन जांच सुनिश्चित की जाए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में गुणवत्तापूर्ण जांच, टीकाकरण और सटीक डेटा एंट्री की व्यवस्था की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, उपचार और बर्थ वेटिंग होम्स में सुरक्षित प्रसव की अनिवार्यता पर जोर दिया। जिला स्तर पर स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभागों के बीच संयुक्त कार्ययोजना बनाकर समन्वय को सशक्त करें।

जीएसटी उत्सव के बीच व्यापार में भारी मंदी, बाजार सुने

माही की गूंज, पेटलावद।

विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी टैक्स स्लेप में कमी कर आम जनता के लिए त्योहारों का तोहफा बताया था। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की नई दरे लागू हो गई। भाजपा नेता,मंत्री सब मिल कर बाजारों में घूम-घूम कर जीएसटी महोत्सव मना रहे है। दूसरी ओर बाजारों से ग्राहक पूरी तरह गायब है और ग्राहकी का भारी अभाव देखा जा रहा है। त्योहारों के ठीक पहले बाजार से रौनक गायब है। शुक्रवार को करवा चौथ को देखते हुए साड़ी और करवा चौथ की सामग्री की दुकानों पर थोड़ी बहुत ग्राहकी देखी गई ,बाकी व्यापार में निराशा का माहौल है। खास कर बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सहित दुपहिया ,चार पहिया वाहनों की बिक्री में भी व्यापार में रौनक अब तक दिखाई नही दे रही है। फसलों को नुकसान से भी व्यापार प्रभावित हुआ है इस बार किसानों को अधिक बारिश के चलते सोयाबीन, मक्का आदि फसलों में पर्याप्त उपज नहीं मिली और नुकसान उठाना पड़ा। बारिश से खराब बची कूची फसल का सही दाम नहीं मिला जिससे बाजारों की रौनक कमजोर होना भी बड़ा कारण है। क्षेत्र के ज्यादातर ग्रामीण, मजदूरी के लिए बहार का रुख कर चुके है जिसके चलते बाजार सुनसान है। दीपावली जैसे त्योहार के करीब आने पर व्यापारियों को ग्राहकी की उम्मीद है। वही आम जनता भी घटी जीएसटी दरों के साथ होने वाले फायदे का इंतजार कर रही है जिसका लाभ अभी तक होता नहीं दिख रहा।

इस तरह से सुनसान पड़े है मुख्य बाजार।

नवीन ग्रीड का किया शुभारंभ

माही की गूंज, सारंगी।

33/11 केवी उपकेन्द्र मठमठ अंतर्गत सारंगी बिजली वितरण केन्द्र का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास विभाग की केबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के द्वारा किया गया। 2.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस उपकेन्द्र से क्षेत्र के 17 ग्राम जिसमें मांडन, डोर,नाहरपुरा,हथिनीपाड़ा, प्रतापपाड़ा, पोलारुंडा , गुणावद, कालारेंगा, बलियापाड़ा, आमलीपाड़ा, केलकुई, तीखी, धावड़िया, कामठिया, बनियाखेड़ा, हनुमंतिया, हिम्मतगढ़ आदि क्षेत्र के किसानों व 38 सौं उपभोक्ताओं को निरंतर विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा। तथा अब कम वाल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। इस दौरान क्षेत्र के नेता, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अस्पताल में रंगाई पुताई के साथ हो रही साफ सफाई

माही की गूंज, खवासा।

राष्ट्रीय गुणवंत आश्वासन मानक भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवाओं की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए एक स्थापित ढांचा है। जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष नई दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की एक पैनल जिला चिकित्सालय के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचती है। साथ ही गुणवंता की जांच की जाती है। अगर कोई भी अस्पताल साफ सफाई के साथ मरीजों को बेहतर सुविधा देते हुए पाया जाता है। तो नई दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनको एक प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाता है। यहां इलाज करने के लिए पहुंचे मरीजों का कहना है कि, अचानक से ही अस्पताल में साफ सफाई के साथ सभी तरह की सुविधा दिखाई दे रही है। लेकिन इतने दिनों से अस्पताल में जिस स्तर की कमी थी वह अब ऊपर से निरीक्षण करने आने वाली टीम को अपनी कमी नहीं दिखे। इस उद्देश्य से अस्पताल में साफ सफाई के साथ पूरी तरह से स्वच्छ बनाने का कार्य डॉक्टर से लेकर एएनएम व खवासा से सटे ग्रामीण अंचलो के उपस्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ सीएचओ आदि को अस्पताल में कार्य के लिए लगा रखा है। वहीं अस्पताल में कमरों के साथ ही जहां पानी के लिए नल की समस्या है। वहां भी नए सिरे से नल लगाने के साथ ही जहां लाइट आदि सुविधा बंद है उसको भी सही किया जा रहा है। मरीज इलाज करवाने आ रहे हैं उनका कहना है कि, इस तरह से अगर हमेशा स्वास्थ्य केंद्र पर साफ सफाई के साथ सभी सुविधा मिले तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी जब बाहर से कोई टीम आती है तभी साफ सफाई के साथ सभी सुविधा मुहईया करवाने का दावा करते है। लेकिन बाद में फिर वही पुरानी वाली स्थिति निर्मित हो जाती है।

खवासा के ग्रामीणों का कहना है कि, जब नई दिल्ली की टीम आए उसके बाद फिर उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या इसी तरह की साफ स्थिति बनी रहेगी या पहले की तरफ फिर आसपास गंदगी के साथ उसी स्थिति में यह अस्पताल देखा जाएगा?

बामनिया में संयुक्त दल द्वारा नमूने लिए

माही की गूंज,झाबुआ।

आगामी दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी चंदर सिंह सोलंकी द्वारा नापतोल विभाग एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन का संयुक्त जाँच दल गठित किया गया। दल द्वारा 8 अक्टूबर को जिले के बामनिया में किराना दुकानों की जांच की गई। जांच में माहेश्वरी किराना, साडूमाता किराना, वैरागी किराना इत्यादि पर निरीक्षण कर तेल, घी, दलिया, सूजी आदि के कुल 8 नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। साडूमाता किराना पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखी पाए जाने की स्थिति में संपूर्ण कन्फेक्शनरी को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

साथ ही नापतोल निरीक्षक कपिल कदम ने निरीक्षण कर मानक घोषणा अंकित न पाए जाने की स्थिति में विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

जाँच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा, वेलसिंह मोरी, नापतोल निरीक्षक कपिल कदम एवं श्रम सहायक संजय पांचाल उपस्थित रहे।

विकृतियों और संदेह के कारण उद्देश्य से विमुख होते युवा

माही की गूंज, झाबुआ।

संकट के समय संवाद संभव नहीं दिखाई देता, तब युवाओं के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की संभावना से नई समस्या का समाधान नए संघर्ष से समाने लाया जा सकता है।

सत्य सदैव विजयी होता है, इसीलिए हम अनंत कालो से विजयादशमी का पर्व मनाते आए हैं। जिसमें बुराई, और झूठ के प्रतिक रावण का पुतला बनाकर दहन किया जाता है और श्री राम के जयकारे के साथ नभ में स्वर गुंजायमान होता है असत्य पर सत्य की जीत होती है। पुरा विमर्श स्पष्ट है मगर फिर भी युवाओं में भटकाव है।

विश्व जिसे जेन जी कहता है वह असमंजस, अकेलेपन, भ्रामक विचार, झूठ और षड़यंत्र का शिकार है क्योंकि उस पीढ़ी में संस्कार परिवार और परंपराओं की शक्ति का अभाव है। आज आंतरिक बिखराव जहां भी दिखाई दे रहा है वहां युवा पीढ़ी अपनेआप में मग्न और अपने ही विचारों से सम्मोहीत होकर अपने में ही आत्मकेन्द्रीत होकर रह गए है। जिसके कारणवश युवा पीढ़ी ने स्वयं के जीवन को एक खेल या एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि, युवा पीढ़ी मोबाइल की गिरफ्त में बूरी तरह से फंस चूकी है। साथ ही इसके यौन विकृतियों से लेकर अस्मिता पर संदेह तक के गंभीर प्रकरण सामने आ चूके हैं।

उद्देश्यों से विमुख हुई व्यवस्था की समस्या का समाधान खोजने के बजाय युवा आक्रमक रुख की ओर मुड़ते जा रहे हैं और दिशा भ्रम होने के कारण वो सिर्फ साधन मात्र बन जाते हैं उन षड़यंत्री लोगों के लिए जो भारत की विकसीत गति पर विराम लगाना चाहते हैं। वो लोग षड़यंत्र इस तरह फैलाते है कि उस आंदोलन में प्रथम दृष्ट्या सभी को लगता है कि आंदोलन की स्थिति युवाओं की हितैषी है परंतु जैसे-जैसे आंदोलन का षड़यंत्र गंभीरता से टुटने लगता है और उसका रहस्य उजागर होकर खुलकर सब के समाने आने लगता है तब पता चलता है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां किस तरह युवाओं को भ्रमित कर बरगलाते हैं और युवाओं के माध्यम से अपने मतलब की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं।

श्रीलंका, बाग्लादेश, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने वाले न तो युवाओं के हितैषी है न ही भारत देश के। षड़यंत्र का हिस्सा बनने वाले भी किसी और के हाथों की कठपुतलिया बने हुए हैं इस बात का अंदाजा भी उनको नहीं लगता हैं। दूर देशों में बैठे षड़यंत्रकारी भारत को बर्बाद करने के विचार को लिए वर्षों से अपनी बुद्धी लगाकर असंख्य धन से भारत के विमर्श को बदलने की कोशिश सतत करते जा रहे हैं, जिसमें अब वे लोग युवाओं को केंद्रीत कर आंदोलन करवा रहे हैं। षड़यंत्रकारी उन भ्रमित युवाओं को चिन्हित कर धीरे-धीरे उन्हें सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी संगठन में जोड़ने लगते हैं, और फिर नीतियों में परिवर्तन करने की तरफ युवाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं और युवाओं का उपयोग करते हुए झूठे षड़यंत्र में फंसा कर आंदोलन की आग में झौंक देते हैं।

संदेह और भ्रम में फंसे युवाओं के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की संभावना को देखते हुए शिक्षा को अग्रणिय रखा जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही प्रत्येक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसी के साथ यह प्रश्न भी अधिकतर उठता है कि शिक्षित बैरोजगार भ्रमित हो रहे हैं वे रोजगार के अभाव में दुषित विचारधारा की मानसिकता में प्रवेश कर विकृतियों को प्रबलता देने में सहयोगी हो रहे हैं।

जहां तक देखा जाए तो समस्या का स्वरुप समय के अनुरुप स्वतः ही परिवर्तित होता जाता है कहीं-कहीं पर समस्या के रुप को जानकर बदला जात है, तब ऐसे में प्रबुद्ध वर्ग को सामने आकर परिवर्तन की गति के अनुमानित होकर समाधान खोजने चाहिए। परिवर्तन की गति का अनुमान आसान नहीं होता यह तेजी से बढ़ती आकांक्षाओं और जटिलताओं को बढ़ाने वाली होती है, इसीलिए यदि संभावनाएं नई है तो समस्याएं भी नई होगी और उन नई समस्याओं का समाधान भी नया ही होगा, जिसके लिए सरकार को सतत प्रयास और सदृढ़ता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। देश के प्रत्येक विद्यालय में नई कौशल शिक्षा को लाना अवश्यक होगा, जिसके कारण शिक्षित बैरोजगार स्वयं को रोजगार विहिन नहीं कह सकेगा। विकसित भारत में युवाओं को आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक स्तर पर देश की आर्थिक स्थिति को बलशाली बनाना होगा।

युवाओं को सुशिक्षित होने के साथ-साथ कौशल और व्यवहार कुशलता में भी पारंगत होना आवश्यक है। इसके लिए घर की शिक्षा जिसमें वेद, ग्रंथ के साथ हमारा इतिहास भी होगा, और जब युवा इतिहास का अध्ययन कर समझेगा तब वह किसी भी प्रलोभन में आ कर भ्रमित नहीं होगा और षड़यंत्रकारियों के उपयोग की सामग्री नहीं बनेगा।

देश में लद्दाख जैसे स्थान पर जब इस प्रकार का आंदोलन हुआ तब उसे भी युवाओं से जोड़ कर प्रस्तुत किया गया और उसके बाद भारत की विचारधारा के विरोधियों ने झूठा विमर्श फैलाने की कोशिश शुरु कर दी और कहने लगे की जैसा श्रीलंका, बाग्लादेश, और नेपाल में हुआ वैसा भारत में भी होगा और युवाओं द्वारा सरकार गिरा दी जाएगी। फिर ज्यों-ज्यों षड़यंत्री आंदोलन के रहस्य से पर्दा हटने लगा तब लोगों के समझ में आया यह अंग्रेजो की उस मानसिकता का असर है जो अवचेतन से झांक कर बाहर आ रही थी। सन् 1931 जे एच हटन द्वारा सेंसस कमिश्नर रहते हुए जनजातीय धर्म के इतने व्यापक मानक तय कर दिए थे कि अधिकतर जनजातीय गणना हिंदू धर्म से अलग हो पाए, किंतु हिंदू महासभा से सार्थक प्रयास से जनजातियों को अपना धर्म हिंदू अंकित करने की प्रेरणा मिली।

रिंकेश बैरागी

अब लद्दाख संकट का संदर्भ यह है कि उसे राज्य का दर्जा चाहिए क्योंकि वहां के लोग यह नहीं चाहते कि गैर जनजातीय लोग वहां आकर बसे। उनको इस बात का डर है कि केंद्र शासित होने पर गैर जनजातीय लोग बसेगे और उनकी संस्कृति का क्षरण होगा, जो की इतना सरल है नहीं जितनी कल्पना की गई। युवाओं के लिए भ्रम का मकड़जाल बनाया और छटी अनुसूची लागु करने पर जोर दिया गया जबकी सीमा क्षेत्र के कारण जिसकी संभावना नहीं के बराबर है।

लद्दाख के युवा एक ओर सभी परियोजना, पर्यटन, उद्योग का विरोध कर रहे हैं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। युवाओं को भ्रमित करके षड़यंत्रकारी अंग्रेजों की उस मानसिकता को सफल करने के प्रयास में लगे हुए है जिसमें जनजातीय समाज को गैर जनजातीय समाज से पृथक करना था।

बहरहाल सारा संसार सत्य पर ही स्थित है, इसीलिए युवाओं को किसी भी आंदोलन में शामिल होने से पहले उसकी जड़, उसकी गंभीरता के साथ उसके इतिहास की गहराई को देखना चाहिए जिससे वे आंदोलन के पीछे छिपे देश विरोधी षड़यंत्रों को सत्यता के साथ समझ सके।

पैसा एक्ट का हवाला देकर मेला निरस्त करने का प्रयास

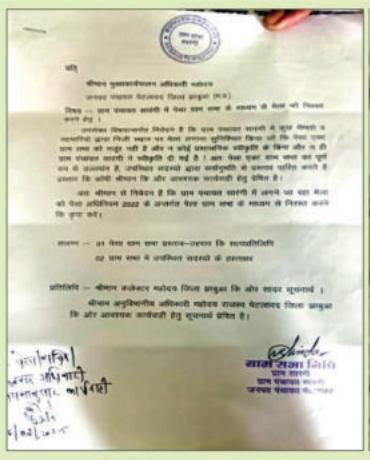

ग्राम सभा का अधिकारियों को प्रस्तुत आवेदन।

अनुमति लेने से पहले ही मेला स्थल पर मेला लगना हुआ शुरू।

माही की गूंज, सारंगी।
संजय उपाध्याय

वर्षों से सारंगी में मेला लगाए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे थे लेकिन मेला आयोजन को लेकर कोई आपसी सहमति ग्राम पंचायत ओर स्थानीय लोगों के बीच नहीं बन रही थी। इस बीच ग्राम पंचायत के कुछ पंचों ओर स्थानीय नेताओं ने मिल कर मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया। लेकिन बिना किसी सक्षम अधिकारी की विधिवत अनुमति के बिना मेला स्थल तय कर मेला लगाने का कार्य शुरू कर दिया। वही मेले को लेकर ग्राम पंचायत दो भागों में बट गई और सरपंच, सचिव सहित पंचायत के कई पंच मेला आयोजन को लेकर विरोध में उतर गए। ग्राम पंचायत सारंगी की ग्राम सभा के माध्यम से मेला आयोजन पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए मेला निरस्त करने की मांग कर ली। दूसरी ओर बिना अनुमति के नियम कायदे ताक में रख कर मेला लगाने वाले आपत्ति के बाद अब मेले को लेकर अनुमति को लेकर हाथ पैर मारते नजर आ रहे है। मठमठ क्षेत्र में आई मंत्री निर्मला भूरिया से मेले की अनुमति दिलवाने के लिए आवेदन निवेदन किया।

जानकारीनुसार बुधवार को आयोजनकर्ता अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंच कर मेले की अनुमति के लिए आवेदन दिया। सरकार पैसा एक्ट लागू कर आदिवासियों के भले की बात कर रही है लेकिन पैसा एक्ट को लेकर कोई बड़ी पहल देखने को नहीं मिली है। सारंगी मेले को निरस्त करने को लेकर पैसा एक्ट को माध्यम बना कर आवेदन ग्राम पंचायत सारंगी सरपंच,सचिव, नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन देकर मेला निरस्त करने की मांग की। आवेदन में बताया गया कि, मेला बिना किसी सक्षम अधिकारी ओर बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के निजी भूमि पर लगाया जा रहा है जो पैसा एक्ट समिति को मंजूर नहीं है। समिति के सदस्यों ने मेला निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया ओर पैसा एक्ट अधिनियम 2022 के नियमो के तहत मेला निरस्त करने हेतु अधिकारियों को लिखित आवेदन पेश करने की मांग की।

15 दिन से ज्यादा का मेला, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी...?

शासन के वार्षिक कैलेंडर में विकास खंड के कई मेले विधिवत दर्ज है जो समय-समय पर प्रशासन की अनुमति के साथ आयोजित होते है। सारंगी में आयोजित होने वाले मेले को लेकर प्रशासनिक कमजोरी खुल कर सामने आई है, आयोजनकर्ता अधिकारियों की नाक के नीचे बिना स्थानीय पंचायत ओर सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना ही मेले को लेकर पूरी तैयारी कर ली ओर बहार से मेला लगाने के लिए सामन भी आना शुरू हो गया। बताया जा रहा है मेला 15 से 20 दिनों तक चलेगा। वही दीपावली जैसा बड़ा त्योहार की चुनौती प्रशासन के सामने है, ऐसे में मेले में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो जवाबदार कौन होगा...? पूरे देश में भिड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अलग-अलग घटनाएं सामने आ रही है जिससे प्रशासन किसी प्रकार की रिस्क लेने पर हजार बार विचार करेगा ये तय है।

स्थानीय व्यापारियों को नुकसान

उधर मेले को लेकर अलग-अलग चर्चा है कई लोग मेले के पक्ष में तो कई मेले के विरोध में है। मेले में केवल झूले-चकरी नहीं बल्कि कई प्रकार के दूसरे व्यापारी भी आएगें जिससे आने वाले त्यौहार पर स्थानीय व्यापारियों के व्यापार में भारी गिरावट होने की संभावना है।

ग्राम पंचायत सचिव हरिराम भूरिया ने कहा कि, जो लोग मेले का आयोजन कर रहे है वो अधिकारीयों के पास गए है, जैसे निर्देश मिलेगें आगे की कार्रवाई की जाएगी।

योगेंद्र सिंह राठौर पूर्व जनपद उपाध्यक्ष पेटलावद ने इस विषय में कहा कि, इस मेले का गांव वालों का भी विरोध है, किसान की फसल को नुकसान हुआ है, फसल की उपज कम बैठी है। यह मेला निजी मेला है ठेकेदारी प्रथा में मेला लगेगा, दुकाने भी सभी ठेकेदार की लगेगी, गांव का व्यापारी एक भी दुकान नहीं लगाएगा इसलिए गांव वालों के साथ हमारा भी इस मेले का विरोध है। तथा बिना अनुमति के लग रहे मेले को तत्काल निरस्त करना चाहिए।

मनमानी का अड्डा एमपीईबी खवासा

माही की गूंज, खवासा।

वास्तविकता यह है कि, अगर कहीं भी कोई अनहोनी किसी कारणवश हो जाए तो उस कारण को अमल में लाकर यह प्रयास किया जाना चाहिए कि, पुनः ऐसी कोई गलती न हो जिससे कोई अनहोनी हो जाए। इसमें जब किसी की जान, जाने जैसी बात होतो ऐसे संवेदनशील मामलों में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। लेकिन मध्यप्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी (एमपीईबी) खवासा कहीं न कहीं गलतियों के बाद भी अपने में सुधार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यानीकि पूर्व में एक से अधिक कई बार विद्युत रिपेयरिंग के दौरान लापरवाही के चलते दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसमें मौत तक कर्मचारियों की हो चुकी है। बावजूद खवासा एमपीईबी में पदस्थ जवाबदार अधिकारी दुर्घटनाओं के बाद भी कोई सबक नहीं ले रहा है और पूरा कार्य आउट सोर्स कर्मचारी के भरोसे होकर मनमानी का अड्डा खवासा एमपीईबी बन चुका है।

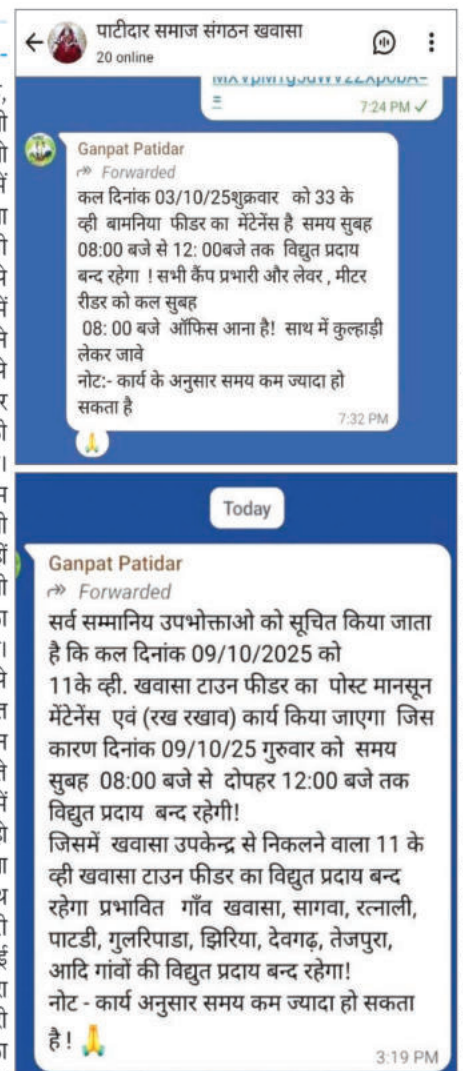

आउटसोर्स कर्मचारी पाटीदार द्वारा अपने कर्मचारी के मेसेज को अपने समाज के ग्रुप में मेसेज फारवर्ड कर अधिकारी अपने कार्य की इतिश्री कर रहे है।

समय-समय पर विद्युत मेंटेनेंस कार्य फीडर स्तर पर चलता है। जब भी उक्त मेंटेनेंस कार्य किया जाना होता है उसकी तैयारी एक से दो तीन पूर्व विद्युत मेंटेनेंस कार्य करने हेतु मुर्त रूप दिया जाता है। तथा ग्रिड इनचार्ज जेई या ई द्वारा विधिवत इसका ग्राफ बनाकर उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना होता है। साथ ही जिस फीडर क्षेत्र में कार्य होता है उस क्षेत्र के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुंचे इसके लिए प्रेस नोट जारी कर अधिकारी द्वारा सूचित करना होता है। लेकिन खवासा विद्युत वितरण कंपनी ग्रीड अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता है। नतीजनत तय है की भविष्य में पुनः दुर्घटना को बुलावा देने का प्रयास माना जा सकता है।

हाल ही में 3 अक्टूबर को 33 के व्ही बामनिया फीडर का मेंटेनेंस का कार्य किया गया जिसमें खवासा क्षेत्र 33 के व्ही के अंतर्गत आता है उक्त विद्युत मेंटेनेंस कार्य का भी कोई प्रेस नोट अधिकारी द्वारा प्रेषित नहीं किया गया। सिर्फ यह जरूर हुआ कि, एक सूचना जो 3 अक्टूबर को 33 के व्ही बामनिया फीडर का मेंटेनेंस था उस हेतु विद्युत कर्मचारी को सोशल मीडिया पर उनके कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला गया। जिसमें 33 के व्ही बामनिया फीडर का मेंटेनेंस है समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक विद्युत प्रदाय बंद रहेगा सभी कैंप प्रभारी और लेबर, मीटर रीडर को कल सुबह 8 बजे से ऑफिस आना है, साथ में कुल्हाड़ी लेकर जावे। नोटः- कार्य के अनुसार समय कम-ज्यादा हो सकता है, उक्त मैसेज सेंड किया गया।

उक्त कर्मचारी को भेजें मैसेज में भी आदेश कर्ता अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया। वहीं एमपीईबी खवासा का एक आउटसोर्स कर्मचारी स्थानीय होकर पाटीदार समाज का है। उक्त आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्थानीय पाटीदार समाज संगठन खवासा का एक व्हाट्सएप ग्रुप में कर्मचारियों को सूचित करने वाला यह मैसेज फॉरवर्ड किया। उसके अलावा कोई सूचना या प्रेस नोट अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाना दुर्घटना को बुलावा देने जैसे ही है।

इसी तरह बुधवार को उसी कर्मचारी ने पाटीदार समाज संगठन ग्रुप में मेसेज फारवर्ड किया, जिसमें भी 11 के व्ही खवासा टाउन फिडर का पोस्ट मानसुन मेंटेनेंस कार्य 9 अक्टुंम्बर के संबंध में मेसेज किया जिसमें 8 से 12 बजे तक विद्युत प्रदाय बन्द रहैगी बताया गया। जिसमें भी किसी भी अधिकारी के आदेश का हवाला नही दिया गया। तथा उक्त जानकारी सिर्फ उक्त ग्रुप तक ही सिमित है। जवाबदार अधिकारी को चाहिए कि, वे इस तरह की लापरवाही न करें और ना ही किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करें।

जानलेवा गहरा गड्ढा मौत को देता आमंत्रण

माही की गूंज, पारा।
गजेन्द्र चौहान

आप सभी जानते है झाबुआ जिले मे कही पर भी दुर्घटना होने जैसी सम्भावना होती है तो जिले मे कोई सा भी विभाग हो, विभाग वाले कभी भी सतर्क नही रहते है। मानो विभाग वाले कुंभ करणीय नींद मे सोये हो ऐसा प्रतीत होता है। जैसे विभाग वालों को बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार रहता है। झाबुआ जिले मे रीत बनी हुई है जिले मे ऐसे कई मामले, घटनाएं होने के बाद विभाग वाले जागते है। जिसके बाद फिर नित नए नियम लागू करते है। मामलो को लेकर फिर वही अपनी ढ़पली अपना राग सुनाते है और थोड़े दिनों के बाद मामले ठंडे बस्ते मे चले जाते है। हम कोई एक विभाग की बात नही करते विभाग कोई सा भी हो विभागों के सुस्त रवैईये के कारण जिले मे पुरा का पुरा बासडा पोला है।

पेंच वर्क कर के फॉर्मेलिटि निभा दी

पारा ग्राम के चारो तरफ की सड़के राणापुर मार्ग से इंदौर मार्ग व टांडा, जोबट, बोरी, झाबुआ मार्ग गांव के चारों मार्ग पर बारिश के कारण पूरी सड़कें गड्ढों में तब्दील होने लगी है। सड़कों में बड़े-बड़े गुड्ढे के कारण दो पहिया वाहनों से रोजाना छुटपुट घटना होने लगी है। बारिश के दिनों में सड़कों में गड्ढे होना कोई नई बात नहीं है हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का पैच वर्क होता आया है। घटिया पैच वर्क होने की वजह से पहली बारिश में ही पेच वर्क उखड़ जाता है। बारिश के बाद अभी कुछ दिनों पहले ही लोक निर्माण विभाग ने गड्ढों में बारीक गिट्टी डालकर गड्ढो का भराव कर फॉर्मेलिटी निभा दी गई। वापस सड़कों में गड्ढे होने लगे।

भारी वाहनों के कारण सड़के उखड़ती है

गांव के चारों मार्ग पर प्रत्येक दिन सैकड़ो लोडेड भारी वाहनों का आवागमन रात-दिन लगा रहता है। अवैध रूप से रेत से भरे लोडेड वाहन ट्रैक्टर, डमफर, बड़े ट्राले आदि के अलावा छोटे-बड़े वाहनों की रोजाना रात दिन आवा जाही लगी रहती है।

झाबुआ मार्ग पर शनि मंदिर के सामने बना पानी निकासी का नाला सड़क से लगे दोनों तरफ जानलेवा गहरे चौड़े गड्ढे जिंसकी गहराई 30 फीट से अधिक है। दलदल व कीचड़ से भरा नाला पिछले कई वर्षों से सूखा पड़ा है यहा छुटपुट घटनाएं हमेशा होती रहती है। गहरे चौड़े जान लेवा दोनों गड्ढो मे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है लकिन इसका समाधान नही किया जा रहा है। लगता है यहा भी विभाग को बड़ी दुर्घटना का इंतजार है इसीलिए सुध नही ली जा रही है।

रात में दोनों ग` नहीं दिखाई देते

दोनों गड्ढे को जब दिन में देखने पर हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। यही गड्ढे रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देते ऐसे में हालात कैसे होंगे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर जिम्मेदार विभाग गड्ढो के आसपास दीवार बनाकर या लोहे की रेलिंग लगाने का कार्य कर दे तो सम्भावित बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है।

परमात्मा के मिलन की दिव्य लीला का वर्णन

माही की गूंज,पेटलावद।

शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में नगर के श्री सरस्वती नंदन स्वामी भजनाश्रम पर आयोजित रास पंचाध्यायी कथा में कथा वाचिका सुश्री वैष्णवी भट्ट ने भगवान श्रीकृष्ण के महारास की अद्भुत महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ÷महारास कोई साधारण घटना नहीं, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन की दिव्य लीला है। कथा मध्य रात्रि तक चली, जिसके पश्चात भजनों के साथ महाआरती और महाप्रसादी का लाभ भक्तों ने लिया। सुश्री भट्ट ने कहा कि ÷भागवत का प्राण रास पंचाध्यायी है और रास पंचाध्यायी का मूल गोपी गीत है। शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्रीकृष्ण ने असंख्य रूप धारण कर प्रत्येक गोपी के साथ रास रचाया था। यह किसी सांसारिक मिलन की नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन की लीला है। सखी भाव में ही महारास का अनुभव संभव है। उन्होंने आगे कहा कि ÷काम वासना और प्रेम में गहरा अंतर है। काम वासना मधु-मिश्रित विष है, जबकि प्रेम दिव्य सुधा है। काम का विषय तृप्ति है तो प्रेम का विषय त्याग। आज की रात्रि में चंद्रमा सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और भगवान श्रीकृष्ण रूपी अमृत मानव को प्राप्त होता है। इसी दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था। सुश्री भट्ट ने मीरा बाई की भक्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि ÷मीरा बाई ने भगवान श्रीकृष्ण को प्रसन्न कर सशरीर गोलोक धाम प्राप्त किया था। कथा श्रवण के पश्चात रात्रि 12 बजे महाआरती का आयोजन हुआ और उपस्थित भक्तों को महाप्रसादी का वितरण किया गया।

संस्कृति गरबा उत्सव में उमड़ी भीड़, इनामों की हुई बारिश

पुष्पा, काकी, जेल कैदी सहित कई तरह के आकर्षक फैंसी ड्रेस में पहुंच कर किया गरबा

माही की गूंज, पेटलावद।

संस्कृति गरबा उत्सव समिति के दो दिवसीय आयोजन में गरबों के रंग ने क्षेत्रवासियों को आनंदित कर दिया। आयोजन की शुरुआत राष्ट्रगान, मां जगदम्बे व भारत माता की आरती के साथ हुई। प्रतियोगिता में बेस्ट गरबा करने वाले में रीना मुकेश परमार रहे जिन्हें स्कूटी उपहार में मिली। बेस्ट ड्रेस में रागिनी ठाकुर को फ्रिज तो बेस्ट कपल के रूप में राहुल वर्मा को एलईडी भेट की गई। आयोजन के दौरान अलग-अलग गेटअप में आए युवाओं ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। पुष्पा 2 फिल्म में अल्लू अर्जुन का माताजी वाले गेटअप में गरबा करने आए प्रतिभागी ने सब का मन मोहा और पुष्पा स्टाइल में सभी को सेल्फी लेने के लिए मजबूर कर दिया।

जानकारी के अनुसार समिति द्वारा गत वर्ष एक दिवसीय गरबा उत्सव रखा गया था। लेकिन शहर के गरबा प्रेमियों की मांग पर इस वर्ष दो दिवसीय गरबा उत्सव का आयोजन किया गया। रात्रि में नगर परिषद रोड पर बने एक पांडाल में शुरू हुए इस आयोजन में संघ के विभाग सह कार्यवाह आकाश चौहान, सेवा भारती के जिलाध्यक्ष हरिओम पाटीदार , पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी, जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी एवं समाजसेवी रितेश निमजा , पार्षद संजय चाणोदिया के साथ समिति के सदस्यों ने आरती उतारने के साथ गरबों की शुरुआत हुई। आयोजन के दूसरे दिन 6 अक्टूबर को इस आयोजन में उमड़ी भीड़ से आयोजक गदगद दिखाई दिए। बड़ी संख्या में महिलाए और पुरुषों ने गरबों में भाग लिया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दो दिवसीय गरबा उत्सव में बेस्ट गरबा खेलने वाले रीना मुकेश परमार को इलेक्ट्रिक स्कूटी दीपक काग से भेंट की गई। इसी के साथ बेस्ट ड्रेस में गरबा खेलने वाली रागिनी ठाकुर को फ्रिज रवि गुर्जर की और बेस्ट कपल में राहुल वर्मा को एलईडी राहुल पाटीदार की ओर दी गईं। जज की भूमिका रश्मि दवे और पायल सोनी ने निभाई। आयोजन में बड़ौदा की टीम ने भी अपनी उम्दा प्रस्तुति दी। वही नगर के कई युवा इस दो दिवसीय आयोजन में अलग-अलग गेटअप में नजर आए उन्होंने दर्शकों को आनंदित किया। बेहतरीन प्रस्तुतियों को देखते हुए समिति द्वारा अन्य इनामों की घोषणा की गई । जिनमें हेमा नलवाया ग्रुप, सिमरन ग्रुप, रानी परमार ग्रुप, माधव कालोनी ग्रुप, पुराना नाका मित्र मंडल और चौधरी परिवार ग्रुप को समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इसी तरह दो दिवसीय इस आयोजन में उम्दा प्रस्तुतियों को देने वाले गौरव दुबे (थांदला) एवं रिया पटेल को विशेष तौर से अनुपम भंडारी , अनिल मुलेवा, सुनील जानी, लोकू परिहार, कपिल राठौड़ ने सम्मानित किया। आयोजन में कमलेश लाला चौधरी, गौतम गेहलोत, पंकज निमजा, शुभम सेन, मुकेश पड़ियार व अन्य का सहयोग रहा।

संपादकीय

बिहार में चुनाव और एसआईटार विपक्ष का हथियार

आखिरकार, चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दो दशक में पहली बार इतनी कम अवधि तथा दो चरणों में मतदान छह व ग्यारह नवंबर को होगा और मतगणना चौदह नवंबर को होगी। विवादों के केंद्र में रही चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर विपक्ष की राजनीति राजग गठबंधन को चुनौती देगी। एक घटक, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जो पलायन व भ्रष्टाचार के मुद्दे को पार्टी का लक्ष्य बता रहे हैं। बहरहाल, लोकसभा चुनाव सात चरण में कराने के खट्टे अनुभवों से सबक लेकर चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की मांग पर विधानसभा चुनाव दो चरणों में समेटने का निर्णय लिया है। लेकिन यह तय है कि जिस तरह आनन-फानन में पर्याप्त तैयारियों की कमी के बीच एसआईआर को अंजाम दिया गया, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उभरते ही रहेंगे। यहां तक कि मामले में बार-बार शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। अभी आयोग को उन लोगों की शिकायत का सामना करना पड़ेगा, जो वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं। बहरहाल, एक बात तो तय है कि दो दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में बने हुए नीतीश कुमार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि राजग नेतृत्व को उम्मीद है कि हाल के दिनों में कराए गए विकास कार्य तथा लोकलुभावनी योजनाओं की बरसात से वोटों की फसल सींची जा सकेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार का जनमानस नीतीश को फिर से गद्दी सौंपता है या फिर उत्साहित महागठबंधन को सत्ता में आने का मौका देता है। कांग्रेस व राजद का कई मतभेदों के बावजूद एकजुट रहना सुशासन बाबू के लिये मुश्किलें जरूर पैदा कर सकता है। इन चुनावों में मोदी-शाह की प्रतिष्ठा का भी मूल्यांकन होगा। नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी इन चुनावों में दांव पर लगी है कि क्या वे दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे।

बहरहाल, इस बार सुशासन बाबू की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, जब विपक्ष ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के सवाल को बड़ा मसला बना दिया है। जिस मुद्दे पर नीतीश अब तक राजद सरकार को जंगल राज बताकर घेरते रहे हैं, वही अस्त्र अब महागठबंधन की ओर से चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष एसआईआर विवादों के आलोक में मतदाताओं में असमंजस की बात कह रहा है। उसकी दलील है कि अब जब चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं विशेष गहन पुनरीक्षण अभी भी न्यायिक जांच के दायरे में है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। दरअसल, 24 जून को चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर अभियान शुरू करने के बाद मतदाताओं की संख्या में खासा फेरबदल होता रहा है। अभियान शुरू करते वक्त बिहार में मतदाताओं की संख्या 7.9 करोड़ थी, फिर एक अगस्त को जारी मसौदा सूची में यह संख्या घटकर 7.24 करोड़ रह गई। मृत्यु,प्रवास और दोहराव सहित विभिन्न आधारों पर 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। अब अंतिम सूची में 7.42 करोड़ मतदाता हैं। मसौदा सूची में 21.53 लाख नाम जोड़े गए हैं और कुल 3.66 लाख नाम हटा दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों की दुविधा दूर करने के लिये चुनाव आयोग से कुछ सवालों का जवाब तुरंत देने को कहा है। निस्संदेह, न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण, एसआईआर में कुछ हद तक पारदर्शिता देखी गई है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग को उन अवैध प्रवासियों की संख्या साझा करने की जरूरत है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि अखिल भारतीय एसआईआर शुरू करने से पहले बिहार से सबक लेकर सामने आई कमियों को दूर करने की दिशा में चुनाव आयोग पहल करेगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि महिलाओं, दिव्यांगों व बुजुर्गों के लिये बड़े पैमाने पर की गयी घोषणाओं का कितना लाभ सुशासन बाबू को मिलता है।

सोयाबीन ठिकाने लगाने को बीन बजाते ट्रंप

आलू-प्याज़ जैसी फ़सल जब मंडी से भी कोई नहीं उठाता, किसान क्या करता है? किसान उसे ट्रैक्टर ट्राली पर लादकर मोहल्ले-मोहल्ले माइक से आवाज़ लगाता हैकृ'पचास रुपये के पांच किलो आलू ले लो... प्याज़ ले लो..।' इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति की हालत ठीक उसी किसान की तरह हो गई है। ट्रम्प भी 'सोयाबीन ले लो...' की विश्वव्यापी गुहार लगा रहे हैं। ट्रम्प पर अमेरिकी सोयाबीन उत्पादकों का ज़बरदस्त दबाव है। ट्रम्प प्रशासन ने मंगलवार को घोषणा की, कि वह प्रभावित किसानों को 12 अरब डॉलर तक की आपातकालीन सहायता प्रदान करेगा। कृषि मंत्री सन्नी पड़्यू ने कहा कि यह योजना, यूएसडीए के कमोडिटी कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को अस्थायी राहत प्रदान करेगी। इस बीच ट्रम्प चीन, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ दीर्घकालिक नीति पर बातचीत करेंगे।

12 अरब डॉलर का भुगतान बिना अमेरिकी कांग्रेस की स्वीकृति के? यह भी ट्रम्प के लिए मुश्किल हालात हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान, किसानों को 23 अरब डॉलर से अधिक की व्यापार सहायता देने के लिए सीसीसी का इस्तेमाल किया था। कमोडिटी क्रेडिट कॉर्पोरेशन (सीसीसी), अमेरिकी कृषि विभाग 'यूएसडीए' की वित्तपोषण इकाई है। यह अमेरिकी राजकोष से 30 अरब डॉलर तक उधार ले सकता है, और किसी भी शुद्ध घाटे की भरपाई बाद में यूएस कांग्रेस (संसद) की हामी से विनियोजित की जाती है। जब से ट्रम्प आये हैं, सीनेट पांच बार वित्तीय प्रस्ताव खारिज कर चुका है।

इलिनोइस विश्वविद्यालय अर्बाना-शैंपेन के एसोसिएट प्रोफेसर जोनाथन कोप्पेस ने एक मेल के ज़रिये जानकारी दीकृ'इस फंड से जो पैसा निकलता है, हर साल शरद ऋतु में फिर से भर दिया जाता है, लेकिन शटडाउन के कारण इसे फिर से नहीं भरा गया है।' अर्थात, यहां खज़ाना खाली है। ट्रंप ने बार-बार कहा है कि हमारा प्रशासन टैरिफ से होने वाली आय का इस्तेमाल किसानों की सहायता के लिए करेगा। लेकिन, किसानों को इस तरह के सीधे भुगतान की वैधानिक सीमा 35 करोड़ डॉलर है। ज़रूरत 12 अरब डॉलर की है, और ट्रम्प की क्षमता 35 करोड़ डॉलर देने भर की है। मामला, सचमुच बुरा फंसा है।

अमेरिकी सोयाबीन के सबसे बड़े विदेशी खरीदार चीन ने आखिरी बार मई, 2025 में अमेरिकी सोयाबीन खरीदी थी। सितंबर में शुरू हुए इस फसल के मौसम के लिए उसने कोई सोयाबीन नहीं खरीदी है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोया किसानों को समझाया, कि हम अभी भी पेइचिंग के साथ सोयाबीन समझौते का प्रयास कर रहे हैं। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक, 'सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़' के स्कॉट कैनेडी ने सोमवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, कि चीन के पास 'दुनिया भर से सोयाबीन खरीदने का ऑप्शन रहता है। चीन पर 55 प्रतिशत टैरिफ लगाना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि टैरिफ के स्तर को फिर से कम करने की आवश्यकता है।'

चीनी राष्ट्रपति शी ने ट्रम्प को सबक सिखाने के वास्ते ब्राजील और अर्जेंटीना को सोयाबीन का ऑर्डर देना शुरू किया है। चीनी वस्तुओं पर ट्रंप के टैरिफ के जवाब में, चीन ने अप्रैल में अमेरिकी सोयाबीन पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया, जिससे उनकी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता और कम हो गई। चीन के अलावा, अमेरिकी सोयाबीन के शीर्ष आयातकों में मेक्सिको, यूरोपीय संघ, जापान और इंडोनेशिया शामिल हैं। अमेरिकी किसान वियतनाम से लेकर नाइजीरिया तक खरीदारों की तलाश कर रहे हैं।

पिछले महीने, आयोवा के रिपब्लिकन गवर्नर किम रेनॉल्ड्स, जो सोयाबीन की खेती पर अत्यधिक निर्भर एक अमेरिकी राज्य है, एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए थे, जिसमें आयोवा के कृषि सचिव माइक नाइग और राज्य के कृषि और व्यावसायिक नेता शामिल थे। इलिनोइस सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य है, लेकिन आयोवा, नेब्रास्का और मिनेसोटा भी बड़े उत्पादक हैं।

ट्रंप की व्यापार टीम चाहती है, कि भारत के कृषि बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाए। लेकिन, भारत में किसान वोट बैंक को ट्रम्प की खुशी में आहुति देने का जोखिम बीजेपी नहीं ले सकती। इसलिए, अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार खोलने के सवाल पर मोदी सरकार कोई फैसला जल्दबाज़ी में नहीं लेना चाहती। वर्ष 2023-2024 में, भारत में लगभग 130?.5 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, जो देश के कुल तिलहन उत्पादन का लगभग एक-तिहाई है। परिणामस्वरूप, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और चीन के बाद भारत, दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बन गया है। फिर भी, भारत ने 2023-24 में 6.25 लाख टन सोयाबीन का आयात किया था।

भारत में, सोयाबीन उगाने वाले प्रमुख राज्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना हैं। सोयाबीन का सेवन दूध के विकल्प के रूप में पीने या पूरक के रूप में भी करते हैं। पौष्टिक होने के साथ-साथ, सोयाबीन के कुछ अन्य लाभ और उपयोग भी हैं। इसे परिष्कृत करके सोया तेल निकाला जाता है, और इसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल ईंधन, मोमबत्तियां, क्रेयॉन और इंजन लुब्रिकेंट बनाने के लिए किया जाता है।

वर्ष 2025 की शुरुआत से, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अमेरिका से 4,00,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा सोयाबीन का आयात किया है। इसी तरह, जून, 2025 में, वियतनाम ने अमेरिकी सोयाबीन निर्यात परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सोयाबीन, मक्का और गेहूं सहित 1?.4 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने का संकल्प लिया गया। अमेरिकी सोयाबीन एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अफ्रीका में मछली के चारे में सोयाबीन के उपयोग को बढ़ावा देने और पश्चिम अफ्रीकी देश को एक प्रमुख कृषि व्यापार भागीदार के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए अगस्त में नाइजीरिया का दौरा किया था।

पुष्परंजन

35 प्रतिशत सोयाबीन की पैदावार वाला ब्राज़ील नंबर वन पायदान पर है। अमेरिका 28 प्रतिशत, अर्जेंटीना 12 प्रतिशत, चीन 5 प्रतिशत, भारत 3 प्रतिशत के आसपास हैं। लेकिन अमेरिकी किसान अब सोयाबीन की खेती का रकबा घटाने लगे हैं। यूएसडीए का अनुमान है कि विपणन वर्ष 2025-26 के लिए सोयाबीन की बुवाई 31 लाख एकड़ घटकर 84 लाख एकड़ रह जाएगी। इस कमी के बावजूद, पैदावार 50?.7 बुशल प्रति एकड़ से बढ़कर 52.5 बुशल प्रति एकड़ होने की उम्मीद है। एक 'बुशल' गेहूं या सोयाबीन 27.22 किलोग्राम के बराबर होता है। सोयाबीन किसान जिस तरह ट्रम्प के गले की हड्डी बन गए, संभव है नवम्बर, 2026 के मिड टर्म इलेक्शन आते-आते सत्तारूढ़ रिपब्लिकन अलोकप्रिय हो जाए। तो क्या, भारतीय रणनीतिकार 3 नवम्बर, 2026 तक ट्रम्प प्रशासन के ज़रिये होने वाले कृषि-व्यापार समझौते को टालते रहना चाहते हैं? ऐसा होना भी चाहिए!

परमात्मा के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जूता?

देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुई एक अप्रत्याशित घटना ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के समक्ष पेश एक वकील, डॉ. राकेश किशोर ने विष्णु भगवान को लेकर गवई द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध स्वरूप जूता दिखाया। इस घटना के बाद आरोपी के जो इंटरव्यू सामने आ रहे हैं उसमें वह कह रहा है, कि उसने परमात्मा के आदेश से यह सब किया है। वह किसी किस्म के नशे में नहीं था। सनातनियों का जो विरोध चीफ जस्टिस द्वारा किया जा रहा था, उससे वह नाराज था और यह सब उसने परमात्मा के कहने से किया है। इस बयान की देश में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। इस घटना के बाद से देश मे गहन बहस छिड़ गई है। क्या असहमति जताने का यह तरीका उचित है। वह भी एक वकील का जिसे मालूम है, यदि कोई ऐसी बात हुई है जो कानून के खिलाफ है तो उसके लिए वह अदालत में ही जाकर अपनी लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन यह वकील बिना पढ़े-लिखे गवारों जैसा यदि व्यवहार करता है ऐसी स्थिति में इसे माफ तो नहीं किया जा सकता है। वकील राकेश किशोर को अपने किये का पश्चाताप भी नहीं है। वह इसको परमात्मा के नाम पर जायज ठहरा रहा है। इस आरोपी वकील के खिलाफ दिल्ली पुलिस में कई शिकायतें की गई हैं। कतिपय संरक्षण होने के बाद इस पर कार्यवाही नहीं हुई। धर्म के नाम पर इसी तरह के आतंक फैलाने का आरोप है। इस घटना के बाद दलित संगठन भी विरोध में जगह-जगह आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी जूते की माला लेकर उसके आवास पर प्रदर्शन किया। वकील राकेश किशोर का तर्क है, यह कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। यह एक ÷दैवीय आदेश÷ का पालन था। उसने दावा किया कि परमात्मा ने उनसे यह कदम उठवाया है, वह स्वयं ÷साक्षी÷ थे। उसका कहना है, चीफ जस्टिस के कुछ कथनों से उसे गहरी पीड़ा हुई, विशेषकर तब जब एक धार्मिक प्रतिमा से जुड़े मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता का उपहास उडाया। साथ ही सीजेआई द्वारा मॉरीशस दौरे के दौरान दिए गए 'देश बुलडोज़र से नहीं चलेगा' वाले बयान से वह व्यथित था। उसका मानना है कि मुख्य न्यायाधीश ÷राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप÷ कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या किसी संवैधानिक संस्था में, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट जैसी प्रतिष्ठित जगह पर, सुप्रीम कोर्ट के वकील का इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य हो सकता है? अदालतें विचार-विमर्श का मंच हैं, अदालतें आक्रोश का मंच नहीं हैं। यदि किसी नागरिक या अधिवक्ता को न्यायपालिका के रुख से असहमति है, तो उसके पास अपील और पुनर्विचार के कानूनी अधिकार मौजूद हैं। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। परंतु मर्यादा और संवैधानिक मर्यादा का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। बार काउंसिल द्वारा डॉ. किशोर के निलंबन का निर्णय इस बात का संकेत है, पेशेवर आचार संहिता को गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं डॉ. किशोर का यह कहना कि उन्हें बिना सुनवाई के दंडित किया गया है। जिस तरह से इस घटना के बाद वह मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं। वह न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ यह भी बता रहा है कि उन्हें इस घटना के बाद कोई पश्चाताप नहीं है। उन्हें यह भी फिक्र नहीं है कि उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। बार काउंसिल ने जो कार्रवाई आनन-फानन में की है। उसमें उसे पता है, जब मामला ठंडा हो जाएगा और वह अपना जवाब देगा तब उसके ऊपर से प्रतिबंध भी समाप्त हो जाएगा। यह आत्मविश्वास उसे कहां से मिल रहा है यह आसानी के साथ समझा जा सकता है।

इस पूरे प्रकरण ने एक गंभीर विमर्श को जन्म दिया है। कुछ समय पहले एक साक्षात्कार में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि उन्होंने राम मंदिर का फैसला परमात्मा से पूछ कर दिया था। क्या धार्मिक भावनाओं और परमात्मा की आड़ लेकर संवैधानिक अधिकारों और न्यायपालिका के अधिकारों को बाधित किए जाने का एक नया दौर शुरू हो गया है। सनातन की रक्षा के नाम पर न्यायालय और संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाना परमात्मा के नाम पर उचित माना जा सकता है? न्यायपालिका पर भरोसा और सम्मान लोकतंत्र की रीढ़ है। आलोचना जरूरी है। उसका स्वरूप विवेकपूर्ण और विधिसम्मत होना चाहिए। सच्चा मनुष्य धर्म वह है, जो संयम सिखाए। संविधान में दिए गए सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार समान हैं। न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह सभी धर्म और सभी नागरिकों के साथ एक सा न्याय करे। सच्चा न्याय वही है, जो संविधान की सीमाओं में रहकर सबको समान रूप से मिले। सुप्रीम कोर्ट में जूता दिखाना, एक मानसिक बीमारी हो सकती है, ÷दैवीय आदेश÷ नहीं हो सकता है। यह लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है। यह घटना इसलिए भी माफी योग्य नहीं है, कि इसे एक सीनियर वकील द्वारा सब कुछ जानते-बूझते अंजाम दिया गया। उसने पुरी की पूरी न्यायपालिका तथा मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के मान-सम्मान पर सीधा हमला किया है। इसके लिए जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो वह दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह स्वीकार करने में अब कोई संदेह नहीं है, कि भारत में अब भीड़-तंत्र का कानून चलेगा। संविधान और लोकतंत्र का अस्तित्व इस भीड़-तंत्र में बनाए रखना किसी के लिए संभव नहीं होगा। एक-एक करके सारी संस्थाओं को कमजोर किया जा चुका है। जो थोड़ी-मोड़ी साख सुप्रीम कोर्ट की बची थी, इस घटना के बाद वह भी खत्म होने की कगार पर है। घटना के बाद जिस तरह से आरोपी परमात्मा का सहारा लेकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि उसे कडा दंड नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में भारत के संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। वर्तमान में यह मानते हुए सच स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सनत कुमार जैन

अपने जुबिन के लिए न्याय चाहता है असम

असम की राजधानी गुवाहाटी से कुछ ही दूरी पर एक गांव में, जो सांस्कृतिक प्रतीक बन गए 21 वर्षीय युवा जुबिन गर्ग का पैतृक ग्राम है, जब उसकी चिता को रोते-सुबकते लोगों के विराट समूह के बीच अग्नि भेंट किया गया तो आसमान 21 राइफल की सलामी फायरिंग से गूंज उठा। इससे पूर्व भूपेन हज़ारिका को 2021 में ऐसा राजकीय सम्मान मिला था।

जुबिन के लिए तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया। जैसे-जैसे आग की लपटें बढ़ती गईं, लाखों प्रशंसक उनकी 'मायाबिनी' के सामूहिक गीत गाते रहे। इस गीत का सार उनके कई अन्य गीतों की तरह न केवल इस गायक सुपरस्टार के शब्दों का जादू लिए था, बल्कि असमिया और गैर-असमिया की पीढ़ियों के साथ उनके अनोखे जुड़ाव को दर्शाता है। गीत के बोल हैं 'इस जादुई रात के बीचोंबीच, मैं दूर से तुम्हारा चेहरा पहचान सकता हूं। तुम चुपचाप मेरे दिल के किसी कोने में समा गए हो, मेरे मुरझाए मन पर ओस की एक ताज़ा बूंद की तरह, चमकती धूप के जैसे, वर्ना तो, मैं बरसों तक तूफ़ान के भंवर में रहा, यूं अंधेरे से मेरी दोस्ती बहुत पहले हो चुकी थी।'

किशोरावस्था में ही जुबीन अपनी पहली एल्बम के साथ असमिया संगीत जगत पर छा गए। हज़ारिका जैसे महान कलाकार की लोक एवं शास्त्रीय संगीत के सम्मिश्रण वाली मौलिक बंदिशें सुनने के आदी श्रोताओं के लिए जुबीन की आवाज़ ताज़गी लिए रही। वो नियम का एक अपवाद थे। उन्होंने गायकी के किसी नियम का पालन नहीं किया, अपने बनाए संगीत, पटकथा पर पेशकारी से जीते-जी किंवदंती बन गए। ज़रा सोचिए, करीब 40 भाषाओं में 35,000 गाने-उनमें एक था फिल्म गैंगस्टर का 'या अली', जिसने उन्हें बॉलीवुड में प्रसिद्धि दिलाई, ऐसी जगह जिसके लिए उन्होंने घर आना छोड़ दिया था। उम्र सिर्फ़ 52 साल रही।

अपने विशिष्ट अंदाज़ में उन्होंने अपना समर्पित प्रशंसक वर्ग अर्जित कर लिया था। खासकर युवाओं के बीच, जो रूढ़िवाद और पूर्वाग्रहों को धत्ता बताने के जुबिन के तरीके से सम्मोहित थी, उनके जोशीलेपन और आमजन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग से भी, राजनीति और राजनेताओं का मखौल बनाने से, बच्चों के साथ मंच पर गाते-गाते उनकी तरह नाचने पर, मदद मांगने वालों के प्रति उदारता से, जानवरों एवं पेड़ों के प्रति प्रेम पर और बड़ा सितारा होने के बावजूद लोगों के लिए उनकी सुलभता से वे मंत्रमुग्ध थे। इन सबके बीच, असमिया संस्कृति और लोगों के प्रति उनका प्रेम चमकता रहा, जिसका वे जमकर बचाव करते और खुलकर प्रदर्शन करते।

असम से बाहर के कई मीडिया टिप्पणीकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों के लिए, न केवल गुवाहाटी में बल्कि असम के गांवों-कस्बों की सड़कों पर उनके गीत गुनगुनाते, रोते या आंसू थामने की कोशिश करते लोगों के विशाल सागर को देखना हैरानीजनक रहा व पूछने लगेकृउनके अविश्वसनीय आकर्षण की व्याख्या क्या है? अपने लोगों के दिलो-जान में इस कदर कैसे समा गए?

इसके अनेक जवाब हैं और शायद कई साल बाद भी हम इसका कोई एक सटीक जवाब न दे पाएं। उनका जादू धर्म, जातीयता, भाषा व क्षेत्र से परे था, जिनका प्रयोग कई राजनेता लोगों को बांटने और घृणा व सांप्रदायिकता भड़काने को करते रहे।

जुबीन, उनके गीतों, संगीत और संदेशों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से, असम के लोगों का उनको श्रद्धांजलि देने को इतनी बड़ी तादाद में उमड़ना पुष्टि करता है कि विभाजन और विखंडन के प्रयासों के बावजूद उनके संगीत ने असम को कलह के वक्त भी बांधे रखा, उस पर मरहम का काम किया। उनके बोल युवाओं और मध्यम उम्र के लोगों व वृद्धों के दिलों को छूते, वे सब जो अनिश्चित और असुरक्षित समय से जूझ रहे, अपने भविष्य को लेकर चिंतित, हिंसा-हानि, सशस्त्र आंदोलनों व सत्ता से परेशान हैं, वे सब चीज़ें जिन्होंने उनकी भूमि और समाज को बर्बाद कर रखा है। जुबिन ने अपने बोलों से उनकी आलोचना करने में कसर नहीं छोड़ी। जब सशस्त्र गुट उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) ने असम के बिहू उत्सव समारोहों में हिंदी गीतों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तो उन्होंने इसकी निंदा की व कहा कि वे ऐसी सांस्कृतिक दबंगई से विचलित नहीं होंगे।

वे राजनेताओं, मंत्रियों का मज़ाक उड़ाते, और एक बार मुख्यमंत्री तक से पूछा, जिन्होंने जुबिन की तरह मंच पर छलांग लगाकर चढ़ते हुए तस्वीरें छपवाईं, 'आप मेरी नकल क्यों कर रहे हैं?' उनके फॉलोअर्स को उनका यह मनमौजी, कटाक्ष युक्त हास्य और बेबाक रंग-ढंग खूब जंचा। इंस्टाग्राम पर 1.28 मिलियन फॉलोअर्स और लोगों के दिलोदिमाग पर किसी राजनेता से कहीं अधिक पकड़ के साथ, उनका रुतबा बहुत बड़ा था। हालांकि राजनीति में नहीं थे तथापि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध कर अपना दृष्टिकोण जाहिर किया और समाजवाद में अपने विश्वास को व्यक्त करते रहते। बताया कि कैसे उन्होंने कभी भाजपा का समर्थन किया था क्योंकि तब लोग असम में 'पोरीबोर्तन' चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनमें कमियां नहीं थीं, कुछ कमजोरियां जिन्हें खुद खुलकर स्वीकार किया।

मेरे (लेखक के) चचेरे भाई, 'डी'कॉम भुयान, जो जुबीन के साथ काम करते थे और अच्छी तरह जानते थे, उनकी अदम्य इच्छाशक्ति के बारे में लिखते हैं 'वे अथक थे। उनके शरीर पर नील पड़ जाते थे, उनका कार्यक्रमों का दबाव बेहद था, फिर भी तत्परता मानो दिव्य जैसी। जहां अधिकांश लोग थकावट या व्यावहारिकता का हवाला देकर हार मान लेते वहीं जुबीन ऐसा नहीं करते। वे तूफ़ान में जीते थे। ऐसी ही एक नींद-विहीन शूटिंग के बाद, वे मेरी ओर मुड़े, उनकी आंखें चमक रही थीं, और मुझ से कहाकृ'डी'कॉम, जीवन अभ्यास के लिए नहीं बना। आप बस इससे बार-बार खेलते हैं, जब तक यह समझ न आए'।

संजोय हज़ारिका

जुबीन का स्वास्थ्य इतिहास यदि इसे भयावह नहीं तो भी आश्चर्यजनक तो ज़रूर बनाता है कि पूर्वोत्तर के इस एकमात्र सुपरस्टार को तथाकथित पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के लिए सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान खुले समुद्र में न सिर्फ तैरने के लिए जाने दिया बल्कि उकसाया भी गया। सिंगापुर पुलिस उनके डूबने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। असम में भी पुलिस जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत और 'उनसे जुड़े किसी संगठन को असम में किसी भी समारोह या उत्सव के आयोजन से रोकने' को काली सूची में डालने की घोषणा की है।

जुबिन के दाह संस्कार के दौरान जिन शख्सियतों की छवियां गौरतलब रहीं - उनमें जुबीन की पत्नी गरिमा का फूट-फूट कर रोना, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का मुश्किल से आंसू रोक पाना शामिल था। जुबिन की मौत हरेक असमिया परिवार के लिए निजी क्षति है। तमाम राजनेता-सत्ताधारी हो या विपक्षी - बिना किसी द्वेष के एक साथ दाह संस्कार में मौजूद थे। अब शासन के सामने बड़ी चुनौती है- जुबीन के लिए न्याय की मांग कर रहे हज़ारों लोगों की बढ़ती नाराज़गी से कैसे निबटा जाए? असम की अधीर आवाज़, जो खामोश हो गई है, लेकिन उसके गीत-संगीत बजते रहेंगे।

फंगस वाले पानी से बन रहा कफ सिरप

माही की गूंज, मंदसौर।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तक दोनों राज्यों में कुल 23 बच्चों की जान जा चुकी है, जिनमें मध्य प्रदेश में 19 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हुई है।

घटनाओं के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब सरकारों ने इस सिरप की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद सिरप बनाने वाली कंपनियां सुरक्षा मानकों और दवा निर्माण नियमों की अनदेखी करती नजर आ रही हैं।

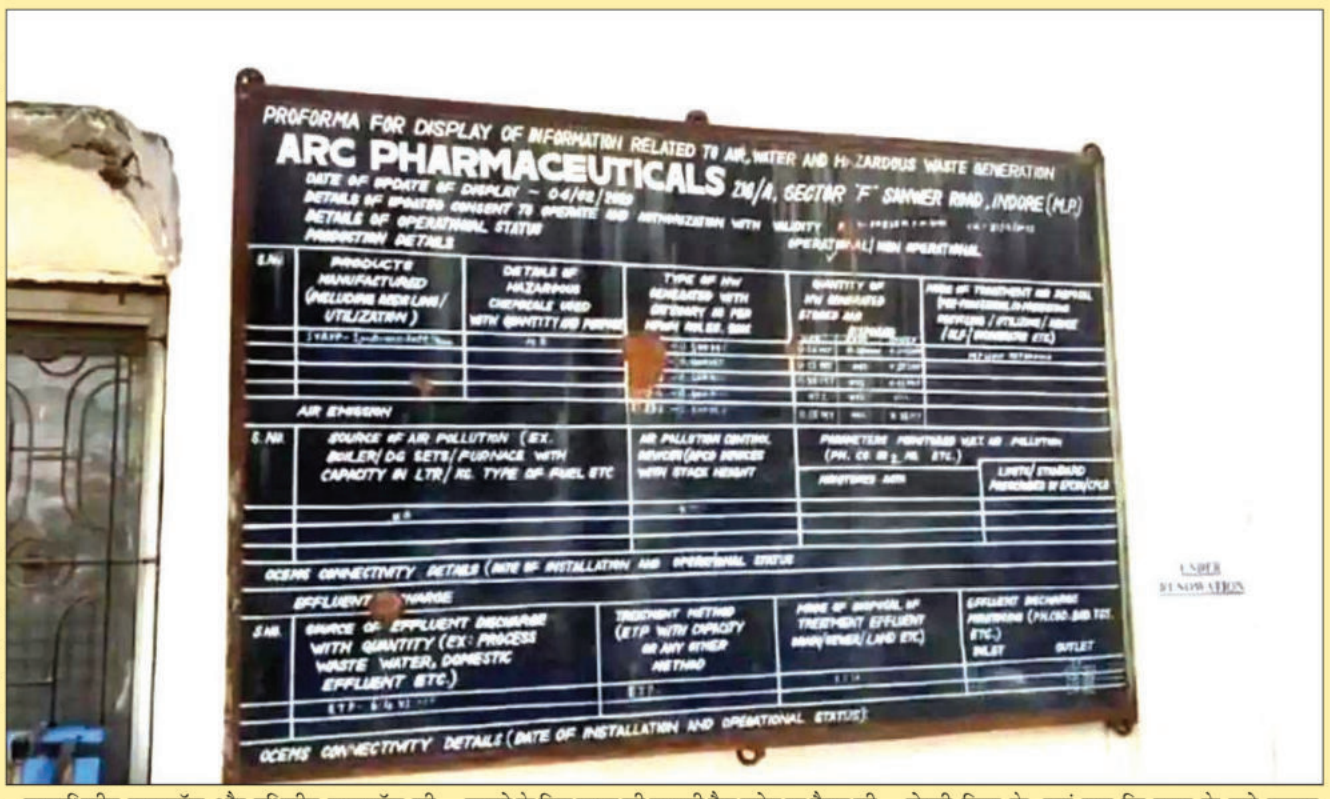

कंपनी की स्थिति देखकर दंग रह गए अधिकारी

इन्हीं घटनाओं के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और इंदौर की एआरसी फार्मास्युटिकल्स कंपनी पर भी शिकंजा कसा गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) के निर्देश पर केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम ने इस कंपनी का रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया। तीन दिन चली इस जांच में कंपनी की स्थिति देखकर टीम के सदस्य दंग रह गए।

89 पेज की रिपोर्ट में खुलासा

जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी में दवा निर्माण से जुड़े मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। यहां फंगस भरे पानी से कफ सिरप बनाया जा रहा था। तैयार सिरप को गंदे प्लास्टिक ड्रमों में रखा गया और बाद में बदबूदार कपड़ों से छानकर बोतलों में भरा गया।

जांच की भी व्यवस्था नहीं

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कंपनी के पास डायएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की जांच की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। इन्हीं रसायनों की गलत मात्रा के कारण बच्चों की मौतें हुई थीं। इसके बावजूद कंपनी ने इन तत्वों की जांच के लिए न तो कोई लैब तैयार की और न ही मानक प्रक्रिया अपनाई।

गैस स्टोव पर बन रही थी चाशनी

जांच टीम को कंपनी परिसर में नीले रंग का एक बड़ा ड्रम मिला जिसमें करीब 50 से 60 लीटर सिरप सस्पेंशन था। जांच में यह भी पता चला कि सिरप में डालने के लिए शकर की चाशनी गैस स्टोव पर तैयार की जा रही थी, जो कि फार्मा निर्माण के सभी नियमों का उल्लंघन है।

इसके अलावा पैरासिटामोल, फिनाइलेफेरिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सस्पेंशन के स्टॉक मिले जिनकी लेबलिंग अधूरी थी। बोतलों पर चेतावनी नहीं दी गई थी कि यह दवा चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है।

कंपनी में रिजेक्ट दवाओं के लिए अलग से कोई स्टोरेज एरिया नहीं था। कर्मचारी बिना यूनिफॉर्म या सेफ्टी गियर के, यहां तक कि बाहर के जूते-चप्पल पहनकर भी दवा उत्पादन कर रहे थे। एयर हैंडलिंग यूनिट और एयर कंडिशनर काम नहीं कर रहे थे, जिससे उत्पादन के दौरान आवश्यक तापमान भी नियंत्रित नहीं रह पाता था।

टीम ने 27 से 29 सितंबर के बीच यह निरीक्षण किया था, जिसके बाद कंपनी में सिरप उत्पादन तत्काल रोक दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गंभीर लापरवाही पर अब सख्त कार्रवाई तय है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

2030-31 तक बिछ जाएगा तीसरा और चौथा ब्राडगेज ट्रैक

माही की गूंज, रतलाम।

दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग के रतलाम रेल मंडल के लगभग 188 किलोमीटर लंबे रतलाम-गोधरा सेक्शन में 2030-31 तक चार ब्रॉडगेज रेल लाइनें हो जाएंगी। खास बात यह है कि ये चार रेल लाइनें गोधरा नहीं उसके आगे वडोदरा तक बिछाई जाएंगी।

अभी इस सेक्शन में डबल यानी दो ट्रैक हैं। अब तीसरा और चौथा ट्रैक बिछाया जाना है। सारा काम प्लानिंग के अनुसार चला तो 2030-31 तक इन तीसरे और चौथी लाइन पर रेलगाड़ियां भी दौड़ने लगेंगी।

पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंगलवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने हरी झंडी दे दी है। 259 किमी लंबे रतलाम-गोधरा-वडोदरा सेक्शन में तीसरी और चौथी रेल लाइन डालने पर लगभग 8885 करोड़ रुपए खर्च होंगे। काम अगले साल शुरू हो जाएगा।

समय-सीमा में काम पूरा करने की रहेगी चुनौती

लगातार बढ़ते जा रहे पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक को देखते हुए रेलवे बड़े स्तर पर तैयार कर रहा है। दिल्ली-मुंबई रूट भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। रेलवे की प्लानिंग पूरे राजधानी रूट में तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की चल रही है। रतलाम मंडल का रतलाम-गोधरा-वडोदरा सेक्शन उसी योजना का हिस्सा है। बढ़ते पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक के चलते यह बहुत जरूरी था। डिमांड भी लंबे समय की जा रही थी। अब रेलवे को कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना होगा क्योंकि प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करना भी एक चुनौती भरा काम है। तीसरी और चौथी रेल लाइन डलने से यात्रियों के साथ रेलवे को भी फायदा होगा। इससे नई यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी तो गुड्स लोडिंग बढ़ने से रेलवे की आय में भी इजाफा होगा।

खाना देर से मिला... वेटर से झगड़ा, ग्राहक ने दागी 4 गोलियां

जबलपुर।

जबलपुर के अभिनंदन होटल में दिनदहाड़े गोलीबारी होने से सनसनी फैल गई। इस घटना में एक बदमाश ने होटल काउंटर पर बैठे मालिक पर एक के बाद एक 4 राउंड फायर किए, जिसका पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। यह सनसनीखेज घटना किसी बड़ी रंजिश का नतीजा नहीं, बल्कि तीन दिन पुराने मामूली विवाद का बदला थी।

मदन महल थाना इलाके के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित अभिनंदन होटल का है। होटल मालिक अश्विन परिया के अनुसार, तीन दिन पहले आरोपी ने होटल में खाना खाया था। खाना देर से परोसे जाने से वह वेटर पर गुस्सा हो गया था और उसका होटल में विवाद भी हुआ था।

इसी गुस्से में आरोपी अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर होटल पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी अभिनंदन होटल में घुसता है और काउंटर पर बैठे मालिक पर फायरिंग शुरू कर देता है।

गोलीबारी के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही गोलियों की आवाजें सुनाई दीं, होटल में खाना खा रहे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे और भगदड़ मच गई। फायरिंग करने के बाद आरोपी पिस्टल लहराता हुआ होटल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

बस स्टैंड पुलिस चौकी प्रभारी जगन्नाथ यादव ने बताया कि गनीमत रही कि फायरिंग में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान शुरू कर दी है और उसकी तलाश जारी है।

पत्नी का गैर मर्द से अफेयर!

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले के कालापीपल थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज अंधे कत्ल का मामला सामने आया था जिसे पुलिस ने मात्र 8 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर रवि भंडारी ने बताया कि मृतक अनोखी लाल, पिता भागीरथ अहिरवार (उम्र 45 वर्ष), निवासी ग्राम भेसाया गड़ा की गला काटकर हत्या की गई थी।जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रेखा बाई और उसका प्रेमी बंटी, पिता कैलाश अहिरवार (उम्र 26 वर्ष) आरोपी हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि रेखा बाई और बंटी का तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने मिलकर अनोखी लाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची। रात को नींद में सोए अनोखी लाल का मुँह और गला दबाकर फिर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने भौतिक साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से मामले को तेजी से सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रक्त परीक्षण एवं पोषण जागरूकता शिविर हुआ आयोजित

माही की गूंज, मंदसौर। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, यूथ रेडक्रॉस, रेड रिबन क्लब तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, मंदसौर के संयुक्त तत्वावधान में, जिला चिकित्सालय के सौजन्य से 8 वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एक दिवसीय ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन एवं थैलेसीमिया परीक्षण शिविर तथा जिला स्तरीय पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य डॉ. टी. के. झाला नें बताया कि यह शिविर महाविद्यालय केडे केयर केंद्र में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपना ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन स्तर एवं थैलेसीमिया परीक्षण कराया। जिन विद्यार्थियों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उन्हें आयरन की गोलियाँ वितरित की गईं।

जादू-टोना के शक में भीड़ ने शख्स को पीट-पीटकर मार डाला

छतरपुर।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के झमतुली गांव में सनसनीखेज कहानी सामने आई है। यहां 60 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति की भीड़ ने पिटाई कर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक का नाम कम्टा आदिवासी था। उसे कुछ ग्रामीणों ने जादू-टोना करने के संदेह में बेरहमी से पीटा।

एजेंसी के अनुसार, इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। खजुराहो के उप-खंड पुलिस अधिकारी मनमोहन बघेल ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें अब हत्या के मामले में पूछताछ के लिए थाने लाया गया है।

पुलिस के मुताबिक कम्टा आदिवासी पहले से ही बुरी आत्माओं को निकालने का कार्य करता था, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने उन्हें जादू-टोना करने के संदेह में निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। जांच के दौरान पूरी सच्चाई सामने आएगी।

झमतुली गांव में आदिवासी समाज में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों और प्रशासन दोनों ही इस मामले में संवेदनशील रुख अपनाए हुए हैं। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने तक इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

महिला प्रशासक रंगे हाथों पकड़ी गई

माही की गूंज, मंदसौर।

मध्य प्रदेश की उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार की महिला प्रशासक हिमांगिनी शर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी प्रभुलाल धनगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रशासक नोटशीट पर साइन करने के लिए 30,000 रुपए की मांग कर रही है। शिकायत का सत्यापन होने के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया और फिर मंगलवार को पहली किश्त 15,000 रुपए लेते ही प्रशासक को पकड़ लिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जैसे ही लोकायुक्त टीम ने हिमांगिनी शर्मा के हाथ पकड़े, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप्पी साध ली। यह कार्रवाई डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल के नेतृत्व में की गई।लोकायुक्त की लगातार कार्रवाई के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

27 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

भोपाल।

मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए 2019 के कानून पर अमल सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस पी एस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ गुरुवार यानी कल सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है।

बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले की सुनवाई कल तक टालने का आग्रह किया इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि नियुक्तियों के एक हिस्से पर जो रोक लगाई गई है उस पर नियुक्ति करने का अदालत स्पष्ट आदेश दे।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 2019 में एक कानून लाकर राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 27 फीसदी कर दी थी। लेकिन इस कानून के अमल पर रोक लगने के बाद नियुक्तियों और प्रवेश प्रक्रियाओं पर असर पड़ा। अब इस कानून को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बता दें सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। अब आज को ये तय होगा कि क्या 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया जाएगा या नहीं।

क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश में फिलहाल ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है. साल 2019 में राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का कानून बनाया। इसे चुनौती देते हुए कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सकारात्मक आदेश दिया, तो राज्य में नियुक्तियों में रुकी प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी। ये फैसला न सिर्फ मध्यप्रदेश, बल्कि ओबीसी आरक्षण नीति पर राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल सकता है।

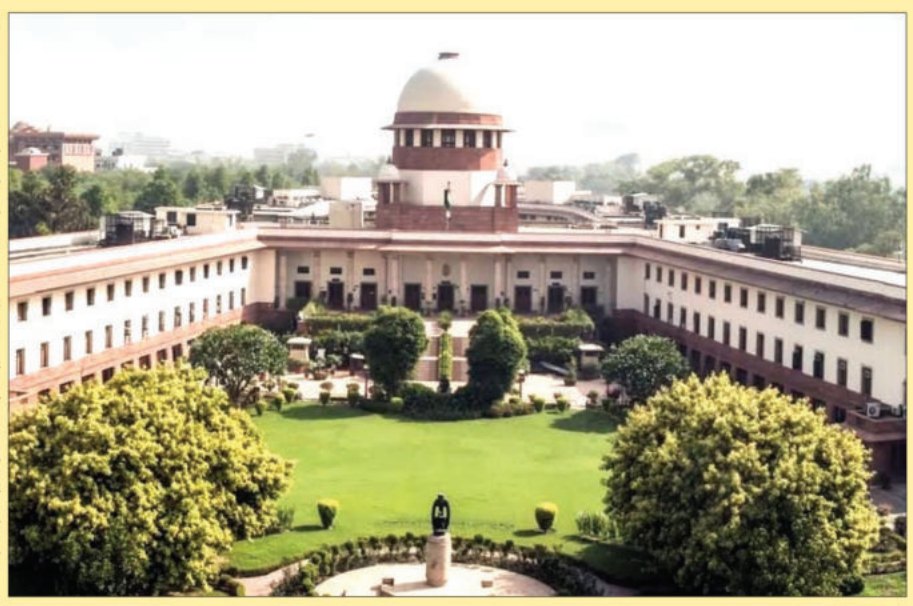

स्कूल से प्राचार्य को हटाए जाने पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी जिले के पाढी विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोकराटा में बुधवार को छात्रों ने प्राचार्य रजनी पड़ियार को अचानक हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सुबह से शाम पांच बजे तक चले इस धरने में छात्रों ने स्कूल के सामने सड़क पर बैठकर प्राचार्य को वापस पदस्थ करने की मांग की।

प्राचार्य रजनी पड़ियार को बोकराटा से हटाकर ग्राम चीकी हाई स्कूल में स्थानांतरित किया गया। इस निर्णय से छात्र हंगामा कर रहे थे। कक्षा 10वीं के छात्र बबलू डावर ने बताया कि प्राचार्य को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि रजनी पड़ियार अच्छी प्राचार्य हैं, जो छात्रों के साथ परिवार जैसा व्यवहार करती थीं और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थीं।

गांव के लोगों ने भी छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया। ग्रामीण रितेश ने बताया कि उन्हें भी इस निर्णय की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि प्राचार्य मैडम ने स्कूल का माहौल बेहतर बनाया था और उनका हटाया जाना छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है।

प्रदर्शन स्थल पर पहुंची तहसीलदार बबलीत बरडे ने छात्रों से बातचीत की और मामले को शिक्षा विभाग तक पहुँचाने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बीईओ राजभीपंवार ने भी मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।

छात्र रितेश और सारिका ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी और प्राचार्य मैडम को वापस नहीं लाया जाएगा, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने तत्काल ट्रांसफर आदेश को निरस्त करने की मांग की।

महिला ने ब्लैकमेल व शारीरिक शोषण का मामला सामने दर्ज

माही की गूंज, खंडवा।

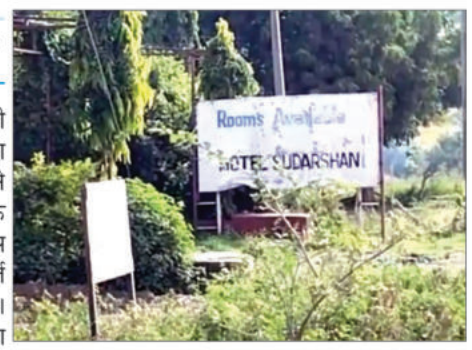

भोपाल की एक शादीशुदा महिला ने खंडवा जिले के मूंदी में पुलिस में मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि सनावद निवासी अजय राठौर ने उसे ब्लैकमेल कर मूंदी के एक होटल में कई बार शारीरिक शोषण किया।

दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और पहले दोस्ती के बाद रिश्तेदारी में भी बढ़ोतरी हुई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

भोपाल के ईदगाह हिल्स में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह सनावद निवासी अजय राठौर से पहले सोशल मीडिया पर मिली थी। महिला का मायका खंडवा के पंधाना में है, इसलिए उसका यहां आना-जाना लगा रहता था। इसी दौरान दोनों का मिलना-जुलना बढ़ा और रिश्तेदारी के दौरान संपर्क में रहने लगे।

महिला ने आरोप लगाया कि जब भी वह भोपाल से पंधाना अपने मायके आती थी, अजय उसे मिलने के लिए मूंदी के सुदर्शन होटल में बुलाता था। महिला का कहना है कि होटल का कमरा अजय ही बुक करता था।

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया, शुरू में जो कुछ हुआ वह आपसी सहमति से था, लेकिन बाद में अजय मुझे डराने-धमकाने लगा और ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने लगा। महिला के अनुसार, आखिरी घटना 14 जुलाई 2025 को हुई थी।

मूंदी थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अजय राठौर सनावद में एक टेंट की दुकान पर काम करता है और घटना के तीन दिन बाद से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पिता की हत्या के मामले में बेटा संदिग्ध, पुलिस ने शुरू की तलाश

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा में एक 62 वर्षीय व्यक्ति के शव मिलने के मामले में हत्या की पुष्टि हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बुजुर्ग के शरीर पर मृत्यु से पहले चोट के निशान थे। लह से वार करके हाथ-पैर तोड़ दिए गए थे, यहां तक कि शरीर की हड्डियां भी फैक्चर थीं।अत्यधिक रक्तस्राव के बाद मृतक ने दम तोड़ा। पुलिस ने मृतक के बेटे को हत्या का आरोपी बनाया है।

दरअसल, एक अक्टूबर को थाना पंधाना क्षेत्र के महादेव बाबा के जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला था। सड़ी-गली लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच की तो असतरिया गांव निवासी मोहन, पिता उदिया जमरे (62), की पहचान हुई।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक और उसके बेटे के बीच विवाद चल रहा था। बेटे ने ही पिता की हत्या की है। मृतक के चार बेटे हैं, जिनमें से तीन ने अपने एक भाई के खिलाफ बयान दिए।

मृतक मोहन जमरे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मृतक मोहन के बेटे सुमेर के खिलाफ मामला दर्ज किया। हत्या का आरोपी सुमेर फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वारदात 30 सितंबर की रात को हुई थी।

पीड़ित के अन्य दो भाई रमेश और कमल ने बताया कि 30 सितंबर की रात साढ़े 8 बजे आरोपी सुमेर ने पिता मोहन के साथ मारपीट की थी। तब से सुमेर फरार है।

परिवार ने बताया कि मोहन के चार बेटे हैं, जिनमें आरोपी सुमेर भी शामिल है। सुमेर नशे का आदि है और उसने दो शादियां की हैं। वह अक्सर शराब पीता था और जमीन को लेकर पिता से झगड़ा करता था। चार भाइयों के बीच एक एकड़ जमीन थी, जिसमें से बाकी तीन भाई मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, जबकि सुमेर शराब के नशे में समय बिताता था।

थ्रेसर की चपेट में आई महिला की मौत

माही की गूंज, खरगोन।

कोयड़ा सूर्वा में थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से 60 वर्षीय महिला सरिता, पत्नी सालू, की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बुधवार दोपहर तब हुआ जब महिला अपने परिजनों के साथ खेत में सोयाबीन निकाल रही थीं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सरिता मशीन के नीचे गिर रहे सोयाबीन के दाने समेट रही थीं। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह थ्रेसर मशीन के पावर टेक-अप सॉकेट में फंस गईं। मशीन में कपड़े फंसने के कारण उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर बमनाला पुलिस चौकी प्रभारी अमित पंवार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाया और पोस्टमॉर्टम के लिए भीकनगांव भेजा।

चौकी प्रभारी ने बताया, ÷पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

सरपंच और साथी रिश्वत लेते गिरफ्तार

माही की गूंज, खरगोन।

लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को छोटी कसरावद ग्राम पंचायत के सरपंच और उनके एक साथी को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मंडलेश्वर रेस्ट हाउस में की गई।

सुरजीत सिंह राठौर सरपंच पति

धर्मेंद्र सिंह राठौर सहयोगी सरपंच

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरपंच सुरजीत सिंह राठौर और उनके साथी धेंद्र सिंह राठौर के रूप में हुई है। इंदौर निवासी सेवानिवृत्त सैनिक अंतिम जेन ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि उनकी कृषि भूमि के एवज में कुल 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इसी मामले में पहली किश्त के रूप में एक लाख रुपए लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की।

करंट लगने से युवक की मौत

माही की गूंज, सेंधवा।

सेंधवा शहर के खेतिया राज्य राजमार्ग पर स्थित एक वस्त्र दुकान की छत पर बोर्ड लगाते समय दो युवक करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में देवझिरी निवासी एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हुआ।

यह घटना फोर्ट गार्डन के सामने स्थित गायत्री गारमेंट्स की दुकान पर हुई। देवझिरी कॉलोनी, सेंधवा निवासी 20 वर्षीय कृष्णा पिता रंजीत मकासरे और सागर परिहार बोर्ड लगा रहे थे, तभी उन्हें करंट लग गया।

दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया। घायल सागर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

घटना की जानकारी मिलने पर मृतक कृष्णा के परिजन और बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मृतक कृष्णा का आज दुकान पर पहला ही दिन था और वह अपने साथी सागर के साथ बोर्ड लगाने गया था। हादसे के कुछ समय बाद दुकान मालिक राकेश वर्मा ने दुकान बंद कर दी।

साहूकारों के शिकंजे से मुक्त नहीं हुए किसान

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण धारणा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ग्रामीण भारत में ऋण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। पहली बात, अब 54.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार केवल औपचारिक स्रोतोंकृक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां, सूक्ष्म वित्त संस्थान से ऋण ले रहे हैं, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ग्रामीण आर्थिक शोषण से बच रहे हैं क्योंकि इन ऋणों पर ब्याज दरें नियंत्रित होती हैं। दूसरी ओर, अभी भी 22 प्रतिशत परिवार अनौपचारिक स्रोतोंकृसाहूकार, दोस्त, परिवारकृपर निर्भर हैं, जहां ब्याज दरें 17-18 प्रतिशत से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, 23.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार दोनों प्रकार के स्रोतों से ऋण ले रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति जटिल हो जाती है।

दरअसल, गांवों में किसानों को औपचारिक ऋण से जोड़ने के मद्देनजर सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था आदि प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। इससे ग्रामीण लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि, डिजिटल उपयोग में वृद्धि, खपत में वृद्धि, ग्रामीणों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, गांवों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार, ग्रामीण भारत के लोगों की पूरक आय में वृद्धि जैसी सकारात्मक पृष्ठभूमि निर्मित हुई है।

वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9.7 करोड़ से अधिक सीमांत किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 20 किस्तों में कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है, जिससे उन्हें खेती-किसानी से जुड़े खर्चों में महत्वपूर्ण राहत मिली है। वहीं पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक देकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। इन सब प्रयासों से ग्रामीण लोगों की खर्च के साथ बचत बढ़ रही है।

चिंताजनक तथ्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी लगभग 22 फीसदी लोग ऋण के लिए साहूकारों और अन्य अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। विशेष रूप से छोटे किसानों को जब आय की अस्थिरता, मौसमी जोखिमों और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ता है, तब वे मजबूरीवश ऊंची ब्याज दरों के बावजूद साहूकारों से ऋण लेने को विवश हो जाते हैं। कई बार सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारक भी साहूकारों से ऋण लेने के मद्देनजर असर डालते हैं। वैसे छोटे किसान औपचारिक स्रोतों से ऋण लेना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार दस्तावेज़ की कमी, गारंटीदाता की कमी एवं अन्य शर्तें बाधा डालती हुई दिखाई देती हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग पचास प्रतिशत कृषि परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को ऋण के लिए संस्थागत बैंकों के साथ-साथ गैर-संस्थागत स्रोतों जैसे साहूकारों और रिश्तेदारों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। कई बार ये छोटे किसान भारी-भरकम ब्याज दर से ऋण चुका पाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में उन्हें ब्याज के बोझ को हल्का करने के लिए फिर ऋण लेना होता है और ऐसे छोटे किसान साहूकारों के ऋण जाल में फंसते चले जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बैंक शाखाओं की संख्या मार्च 2010 के 33,378 से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 56,579 हो गई है। इसके साथ ही सहकारी समितियों का नया विस्तार दिखाई दे रहा है। ऐसे में साहूकारों और अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता घटाने के लिए दूसरे कदम भी उठाने की जरूरत है।

छोटे ऋणों और कम अवधि के ऋण वाली कई योजनाएं तैयार करके साहूकारों पर निर्भरता कम करनी होगी। ग्रामीण ऋण लागत कम करने और विश्वास बढ़ाने के लिए तकनीक का लाभ उठाया जाना होगा। औपचारिक ऋणों के लिए बेहतर प्रोत्साहन और डिजिटल उपकरणों से लैस बैंक प्रतिनिधियों को ग्रामीण परिवारों और संस्थानों के बीच समन्वय का माध्यम बनाया जाना होगा। इसके साथ ही, वित्त-तकनीक कंपनियों द्वारा ग्रामीण कर्ज धारकों के लिए विश्वसनीय क्रेडिट प्रोफाइल तैयार करने के लिए वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग डेटा का उपयोग किया जाना होगा।

जयंतीलाल भंडारी

गांवों में साहूकारों पर ऋण निर्भरता की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसायों को विश्वसनीय संस्थागत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु लक्षित नीतिगत उपाय सुनिश्चित किए जाने होंगे। खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतिम छोर तक मजबूत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की भूमिका को प्रभावी बनाना होगा। गांवों में तरलता संबंधी चिंताएं दूर करने के लिए एनबीएफसी के लिए एक मजबूत पुनर्वित्त सुविधा तत्काल सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत प्रतिभूति हितों को लागू करने के लिए ऋण राशि की सीमा को और घटाना अत्यधिक लाभकारी कदम होगा।

सरकार ने किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए जो कानून बनाए हैं, उनके पर्याप्त परिपालन पर ध्यान देना होगा। गांवों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का तेजी से विस्तार करना होगा, जिससे छोटे किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाई जा सकेगी।

20 मौत के बाद जागा प्रशासन

माही की गूंज, उज्जैन।

बुधवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अचानक अलर्ट मोड में दिखा। वजह थी, छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में जहरीले कफ सिरप से हुई मासूम बच्चों की मौतें। इन घटनाओं के बाद सरकार ने निर्देश जारी किए और उज्जैन प्रशासन ने शहर भर में मेडिकल दुकानों और क्लिनिकों की जांच शुरू कर दी।

फ्रीगंज इलाके में टीम ने की जांच

सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल ने अपनी टीम के साथ फ्रीगंज इलाके में कई शिशु रोग विशेषज्ञों के क्लिनिक और दर्जनों मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। टीम प्रतिबंधित सिरप की तलाश में थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहरीली दवाएं यहां न बिकें। जांच के दौरान दो दुकानों से संदिग्ध सिरप बरामद हुए जिन्हें लैब जांच के लिए भेजा गया है।

प्रतिबंधित सिरप की तलाश जारी

राज्य भर में जहरीले कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने कुछ सिरप पर प्रतिबंध लगाया है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। उज्जैन में प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि प्रतिबंधित ब्रांड की दवाएं दुकानों में न पहुंचें।

डॉक्टरों के क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स की जांच

फ्रीगंज में टीम ने पाटीदार मेडिकल, केयर एंड क्योर मेडिकल और डॉ. रवि राठौर के क्लिनिक पर जाकर रिकॉर्ड चेक किए। अधिकारियों ने दवा के बिल और स्टॉक की जांच की, लेकिन किसी भी जगह पर ÷कोल्ड्रिफ÷ या ÷रिलीफ÷ जैसे प्रतिबंधित सिरप नहीं मिले। टीम ने सभी मेडिकल संचालकों को सख्त चेतावनी दी कि वे प्रतिबंधित सिरप की बिक्री न करें।

दो दुकानों से सैंपल लिए गए

जांच दल ने पुराने शहर के मुसद्दीपुरा स्थित सुनील मेडिकल स्टोर और छत्री चौक के शंकर मेडिकल स्टोर से तीन कफ सिरप के नमूने लिए। इन सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। वहीं, बाकी मेडिकल दुकानों से भी अवमानक दवाओं की जानकारी ली गई।

जांच लगातार जारी रहेगी - सीएमएचओ

सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल ने बताया कि, मंगलवार को भी करीब 20 मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे गए थे। जांच आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर कोई प्रतिबंधित दवा बिकती पाई गई, तो कड़ी कार्रवाई होगी।

दीपावली से शुरू होगी लड्डू प्रसाद की कैशलेस बिक्री

माही की गूंज, उज्जैन।

ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद काउंटरों पर दीपावली से कैशलेस की सुविधा प्राप्त होगी। दर्शनार्थी क्यूआर कोड से भुगतान कर लड्डू प्रसाद खरीद सकेंगे। इस व्यवस्था से दर्शनार्थियों को काफी सुविधा होगी। मंदिर कर्मचारियों को भी खुल्ले पैसों की समस्या से निजात मिलेगी। महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह सुविधा शुरू होने में एक पखवाड़े का समय लग सकता है।

महाकाल मंदिर समिति भगवान महाकाल के भोग प्रसाद के रूप में भक्तों को शुद्ध देशी घी से बने बेसन के लड्डू का विक्रय करती है। मंदिर परिसर स्थित काउंटरों से भक्तों को लड्डू प्रसाद का विक्रय किया जाता है। अभी तक लड्डू प्रसाद की बिक्री नकद होती है।

क्यूआर कोड से दान भी कर सकेंगे भक्त

महाकाल मंदिर समिति क्यूआर कोड से लड्डू प्रसाद की बिक्री शुरू करने के साथ दान के लिए भी इस सुविधा को लागू करने की तैयारी कर रही है। मंदिर परिक्षेत्र में जगह-जगह बड़े-बड़े क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। मंदिर समिति ने यह योजना पहले भी लागू की थी। उस समय दान के लिए लगाए गए क्यूआर कोड में एक कर्मचारी ने अपना नंबर डाल दिया था।

मामले में जांच भी बैठाई गई थी, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो पाया था। मंदिर से जुड़े जानकारों का कहना है कि नए अधिकारियों को इस पूरे मामले की पड़ताल के बाद ही इस प्रकार की योजना शुरू करना चाहिए।

स्लीपर बस में तस्करी का भंडाफोड़

माही की गूंज, धार।

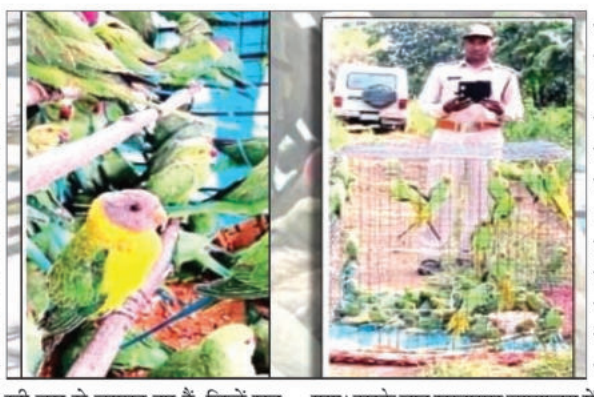

जिले में वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्लभ प्रजाति के 135 तोतों को बरामद किया और उन्हें तस्करों से आजाद कर जंगल में छोड़ा है। ये तोते यूपी से गुजरात जा रही बस से बरामद हुए हैं, जिन्हें सब की नजर से बचाकर चोरी-छुपे ले जाया जा रहा था। तस्करों ने तोतों को छोटे पिंजरों में कैद कर रखा था, जिससे उनकी हालत खराब हो गई थीं। इस दौरान दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

2 तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ जारी

जानकारी के अनुसार वन अमले को मुखबिर से सूचना मिल थी कि, एक वोल्वो बस जो यूपी से अहमदाबाद जा रही है, उसमें तोतों की तस्करी की जा रही है। सूचना के बाद डीएफओ विजयनंथम टीआर के मार्गदर्शन में टीम बनाई गई।इंदौर-अहमदाबाद हाइवे पर भोपावर चौकड़ी के पास बस जीजे 27 वी 9782 आती दिखाई दी। इस बस को रोककर वन अमले ने तलाशी ली। बस की डिग्गी में एक बड़ा बॉक्स (पिंजरा) रखा था। जिसे नेट से ढक रखा था। इसमें चार प्रजाति के तोते कैद थे। कार्रवाई में दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए रेंज कार्यालय सरदारपुर लाया गया। इसके बाद सरदारपुर न्यायालय में पेश किया गया एवं रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है।

जंगल में ले जाकर छोड़ा, कुछ की हुई मौत

कार्रवाई के दौरान बस से 135 तोते बरामद हुए हैं। इनमें चार अलग प्रजाति एलोक्विंसड्रिना, प्लम पैराकीट, ग्रे पैराकीट और रोज़ रिंग्ड पैराकीट के जंगली तोते निकले, जिन्हें पिंजरे में बंद कर रखा था। कुछ तोते मृत पाए गए, जिनका वेटरनरी डॉक्टर दिलीप गामड़ द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया। वहीं जिंदा तोतों को वन अमले ने जंगल में ले जाकर छोड़ा। कार्रवाई के दौरान एसडीओ संतोष रन्सोरे सहित स्टाफ जिसमें विक्रम निनामा, जोगड़ सिंह जमरा, अनिल कटारे, मनीष पाल ,अमित मालवीय, रमेश मेड़ा आदि मौजूद थे।

जागरूकता व स्वास्थ्य शिविर का किया शुभारंभ

माही की गूंज, अलीराजपुर।

डॉ. दिव्या गुप्ता के मार्गदर्शन में रूपांतर नेचर एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सहायक संस्था के रूप में ज्वाला महिला समिति हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से जिले के आकांक्षी विकासखंड उदयगढ़ में महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु जागरूकता व स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। जिसमे मैमोग्राफी, शुगर, हीमोग्लोबिन सलाह, महिला स्वास्थ्य जागरूकता इत्?यादि का परीक्षण शिविर के माध्यम से किया गया। अरविंदो के उम्मीदों वाली बस के माध्यम से चार दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया हैइस दौरान अनुविभागीय अधिकारी वीरेन्द्र सिंह बघेल, जनपद सीईओ माया बरिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या नलवाया, जिला पंचायत सदस्य मांगीलाल चौहान , जनपद सदस्य श्रीमती विजू मुवेल सहित आकांक्षी ब्लॉक समन्वयक डॉ. पुखराज सहित स्वास्थ्य विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

साल में एक दिन खुलता है चौथ माता का ये मंदिर

माही की गूंज, उज्जैन।

इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्रीगणेश और चंद्रमा के अलावा चौथ माता की पूजा भी की जाती है। हमारे देश में चौथ माता के बहुत ही कम मंदिर हैं।

मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट जीवनखेड़ी गांव में भी चौथ माता का एक अनोखा मंदिर है। खास बात ये है कि ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन करवा चौथ पर ही खुलता है। अन्य समय ये मंदिर बंद रहता है। करवा चौथ पर यहां सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ती है।

364 दिन आराम करती हैं चौथ माता

उज्जैन के जीवनखेड़ी में स्थित ये मंदिर प्रदेश का एक मात्र चौथ माता का मंदिर है। कहते हैं कि साल के 364 दिन चौथ माता आराम करती हैं सिर्फ करवा चौथ के दिन ही वे अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। ये मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है। 25 साल पहले यानी साल 2000 में ही इसका निर्माण किया गया है। इस मंदिर में चौथ माथा के अलावा देवी पार्वती, ऋद्धि-सिद्धि और संतोषी माता की प्रतिमा भी स्थापित है।

यहां का प्रसाद भी खास

करवा चौथ पर जब ये मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है तो इस मौके पर खास तरह का प्रसाद दिया जाता है। मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले माता की विधि-विधान से पूजा की जाती है, इसके बदा दर्शन करने वालों भक्तों को माता की चुनरी, चमत्कारी सिंदूर और सिद्ध किए गए रुद्राक्ष दिए जाते हैं। मान्यता है कि ये चीजें बहुत ही दिव्य होती हैं जो किसी की भी किस्मत चमका सकती है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या भी इस दिव्य प्रसाद से दूर हो जाती है।

तीन रूपों में दर्शन देती हैं माता

करवा चौथ पर माता के तीन अलग-अलग रूपों में श्रृंगार होता है। सुबह सबसे पहले माता को बार रूप में सजाया जाता है, दोपहर में किशोरी रूप में और शाम को माता का एक दिव्य रूप देखने को मिलता है। यहीं कारण है करवा चौथ के दिन यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर-दूर से भक्त यहां माता के दर्शन करने आते हैं। साल भर शांत रहने वाला ये मंदिर करवा चौथ पर भक्तों के जयकारों से गूंज उठता है।

पुलिस को 'अपशब्द' कहने वाले युवक ने की आत्महत्या

माही की गूंज, उज्जैन।

सोशल मीडिया पर पुलिस को अपशब्द कहकर चुनौती देने वाले युवकों में से एक अभिषेक चौहान ने बुधवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद नाराज परिजनों ने चिमनगंज मंडी चौराहे पर शव रखकर नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया। अभिषेक के साथी और परिजनों ने पुलिस पर रिश्वत मांगने और प्रताड़ना के आरोप लगाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच की जाएगी।

दरअसल, यह मामला दो दिन पहले की पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। विराटनगर में रहने वाले अभिषेक चौहान ने अपने साथी विक्की राठौर के साथ करीब एक सप्ताह पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में अभिषेक पुलिस को अपशब्द कहते हुए चुनौती दे रहा था कि अगर पुलिस उसे जेल भेजेगी, तो उसका पिता उसे छुड़ा लेगा।

वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार शाम क्राइम ब्रांच ने अभिषेक और विक्की को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की थी। पुलिस ने दोनों युवकों को सबक सिखाने के लिए माफी मंगवाकर उसका वीडियो भी बनवाया था।

मंगलवार को दोनों की जमानत होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया था। इसी बीच, अभिषेक चौहान ने बुधवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे नाराज परिजनों ने चिमनगंज मंडी चौराहे पर शव रखकर नारेबाजी और चक्काजाम किया। अभिषेक के साथी विक्की राठौर ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों ने चिमनगंज थाना पुलिस पर मारपीट और एक सब-इंस्पेक्टर पर 40 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। अभिषेक के पिता का कहना है कि पुलिस ने उनसे एक-एक लाख रुपये मांगने की बात कही थी।

अभिषेक सरिया सेंटिंग का काम करता था और तीन बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का क्यों विरोध कर रहे किसान...?

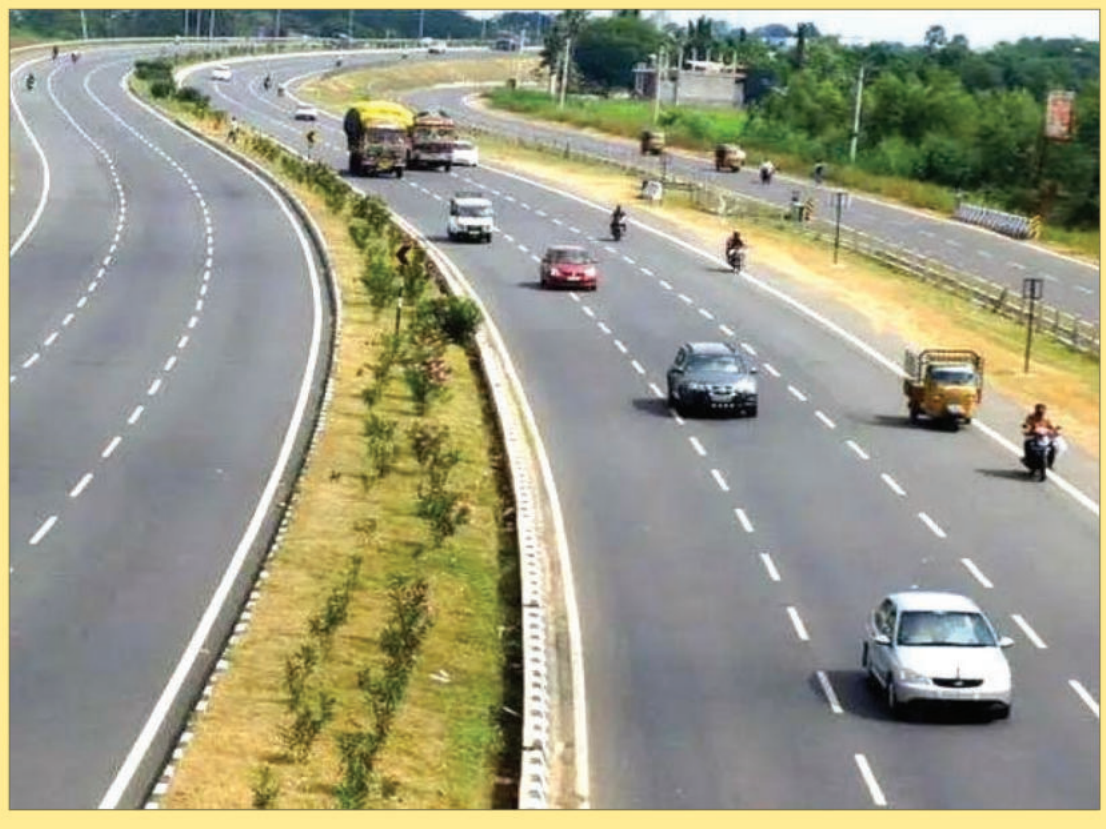

माही की गूंज, उज्जैन।

सिंगस्थ के मद्देनजर शासन ने इंदौर से उज्जैन के बीच सड़क बनाने की मंजूरी दी है। इसे ग्रीन फील्ड कॉरिडोर नाम दिया गया है। इसमें 28 गांवों की जमीनें अधिगृहित की जा रही हैं। जिसमें सांवेर और हातोद तहसील के 20 गांव हैं। बाकी गांव उज्जैन जिले के हैं।

दरअसल, इस सड़क की चौड़ाई की जद में कई किसानों की जमीनें आ रही हैं। इस सड़क का सर्वे शुरू हो गया है। जिसका विरोध शुरू हो गया है।

पैदल मार्च निकलेगा

ऐसे में अब इस प्रोजेक्ट का किसान विरोध कर रहे हैं। बुधवार को कई किसान इसका विरोध करने के लिए ट्रैक्टर से इंदौर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने हातोद से इंदौर तक ट्रैक्टर रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर गांधी नगर, सुपर कॉरिडोर, नावदा पंथ के साथ सिरपुर पहुंच रहे है। यहां टैक्टरों को खड़ा कर कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकलेगा।

क्या है ग्रीन फिल्ड कॉरिडर

दरअसल, उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ के चलते शासन ने इंदौर से उज्जैन के बीच सड़क बनाने की मंजूरी दी है। इसे ग्रीन फील्ड कॉरिडोर नाम दिया गया है। इसमें 28 गांवों की जमीनें अधिगृहित की जा रही हैं। जिसमें सांवेर और हातोद तहसील के 20 गांव हैं। बाकी गांव उज्जैन जिले के हैं। यह सड़क हातोद से कांकरिया, अजनोद, चंद्रावती गंज होते हुए उज्जैन में चिंतामण गणेश मंदिर वाले क्षेत्र से निकलेगी।

क्यों विरोध कर रहे किसान

बता दें कि इस सड़क की चौड़ाई की जद में कई किसानों की जमीनें आ रही हैं। इस सड़क का सर्वे शुरू हो गया है। जिसका विरोध शुरू हो गया है। किसानों का कहना है कि उज्जैन जाने के लिए इंदौर की सड़क को छह लेन किया जा रहा है। उज्जैन देवास इंदौर रोड भी फोरलेन बन गई है। इसके बाद अब नई सड़क की आवश्यकता नहीं है। बेवजह सिंहस्थ के बहाने गांवों में किसानों की जमीन ली जा रही है।

423 करोड़ की बनेगी नई सड़क पर जुगाड़ कर पुराने पुल को नया बताकर निर्माण कार्य की इतिश्री की जा रही

– जुगाड़ कर पुराने पुल में पाईप का टुकड़ा जोड़ पुल चौड़ा कर बनाई जा रही साईट की बिना सरिये सीसी निम्न स्तर की दिवार बनाकर ठेकेदार पुराने पुल को पुरा नया बताने का कर रहा कुकृत्य।

माही की गूंज, खवासा। सुनील सोलंकी

झाबुआ-रतलाम मार्ग करवड़, बामनिया, थांदला होकर जा रही सड़क मार्ग का नवीनी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जो की थांदला से खवासा की और कार्य की शुरुआत की गई है जिसमें थांदला से सुजापुरा तक चोडीकरण कर बेस कार्य कर दिया गया है। बारिश में कार्य को विराम देकर पुनः निर्माण कार्य की शुरुआत की जा रही है जिसमें जहां रास्ते में संकीर्ण पुल है या कोई पुल है तो उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है।

उक्त पुल निर्माण कार्य में अनियमितताएं, मनमानी व निर्माण का स्तर निम्न है यह देखा जा सकता है। रतलाम-झाबुआ उक्त सड़क मार्ग बीलो टेंडर के साथ 423 करोड़ में किसी हरियाणा की हार्दिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण कार्य का ठेका लिया है जिसकी सड़क चौड़ाई 10 मीटर की रहेगी।

हार्दिक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा उक्त मार्ग पर संकीर्ण पुल निर्माण का कार्य देखने पर पता चलता है कि, वह उक्त सड़क निर्माण में कितना बड़ा घाल-मेल कर भ्रष्टाचार को अंजाम देकर निम्न स्तर का कार्य करेगा जो एक संकेत के रूप में सामने आ रहा है।

नई सड़क निर्माण के साथ तय है पुराने जो भी सक्रिय पुल या अन्य पुल है जिनकी समयअवधि भी पूरी हो गई होगी और ऐसे में सभी रास्ते के आने वाले पूल को नई डिजाइन व नई गाइडलाईन अनुसार बनाकर उसपर पक्की सड़क बनाई जाना चाहिए।

परंतु यहां छोटे-छोटे पुल में ही निर्माण करने वाली कंपनी शुरुआती दौर में ही अपने भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करते नजर आ रही है। पुल को तोड़कर नए पाइप डाल वर्तमान में 10 मीटर की चौड़ाई अनुसार सड़क वाले इन पुलों को चौड़ा बनाकर नया निर्माण किया जाना चाहिए। परंतु ठेकेदार द्वारा पुराने पुल को नहीं तोड़कर अपना जुगाड कर एक दीवाल आगे बनाकर पुराने पुल के पाइप के साथ नया पाइप का टुकड़ा जोड़ यह जुगाड़ वाला आधे नए पुल के साथ पूरे पुल को नया बताने का प्रयास ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। जो एक दीवाल पाइप फिक्सिंग हेतु जो दीवाल सीमेंट, कंक्रीट की बनाई जा रही है जिसमें सरिया का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। तय है बिना सरियों से आधे पाइप के टुकड़े को फिक्स करने वाली बन रही है यह सीसी दीवार बिना सरियों के मजबूती कैसे रहेगी...? इसका जवाब किसी इंजीनियर से नहीं बल्कि किसी अनाड़ी से भी पूछा जाए तो उसका जवाब दे सकता है। तय है उक्त रतलाम-झाबुआ सड़क 10 मीटर चौड़ाई होकर यह 8वे से जाकर मिलेगी। ऐसे में उक्त सड़क पर भारी वाहनों की भी आवाजाही बढ़ेगी। ऐसे में हार्दिक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा शुरुआती दौर में ही किये जा रहे अधूरे पुल के निर्माण को पूरा नया निर्माण बताकर व निम्न स्तर का कार्य कर भविष्य में अनहोनी को निमंत्रण दे रहा है।

जब हमारा प्रतिनिधि उक्त मार्ग पर बन रहे छोटे पुल के निर्माण की हकीकत देखने पहुंचा तो सामने आया कि, हार्दिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट विजिट के इंजीनियर मनोजसिंह उक्त निर्माण खड़े रहकर करवा रहे थे। उनसे परिचय किया और जानकारी मांगने पर जानकारी देने से मना कर दिया। जब निर्माण कार्य का फोटो, वीडियो प्रतिनिधि लेने लगा तो इंजीनियर साहब हमारे प्रतिनिधि को फोटो, वीडियो लेने से मना करते रहे। जब फोटो, वीडियो ले लिए तो इंजीनियर साहब कहने लगे, आप जो रिपोर्ट बनाएं उसे हमें बताना और खबर पॉजिटिव ही लिखना।

निर्माण में सामने आया कि, पुराने पुल को यथावत रख बिना किसी मजबूत बेस के सड़क चोडीकरण अनुसार एक्स्ट्रा पाइप का टुकड़ा पुराने पाइप से जॉइंट कर, आगे पाइप के मुंह की और बिना सरिये युक्त निम्न स्तर की सपोर्टिंग साईड दीवाल बनाकर। पुराने पुल को जुगाड़ के साथ बनाकर पूरे पुल को नया बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए मौके पर उपस्थित कंपनी के इंजीनियर साहब कंपनी की अनियमिताओं को दबाने का प्रयास प्रतिनिधि के समक्ष किया।

वही एमपी आरडीसी धार डिवीजन के अधीन बन रहे उक्त सड़क मार्ग की जानकारी लेने हेतु एमपी आरडीसी धार के सब इंजीनियर रामगोपाल हटिला के मोबाइल नंबर 7000617757 व एमपीआरडीसी धार डिवीजन के जनरल मैनेजर अमित भूरिया से मोबाइल नंबर 9131753817 दोनों से फोन पर हमारे प्रतिनिधि ने संपर्क करने का प्रयास किया। परंतु टूकॉलर पर शायद पत्रकार होना देख फोन अटेंड नहीं किया गया।

बदनावर-टिमरवानी फोरलेन चिन्हांकन प्रक्रिया

ग्राम सभा की अनुमति के बिना अधिग्रहण प्रक्रिया पर ग्रामीणों ने जताया विरोध

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

बदनावर-टिमरवानी फोरलेन निर्माण के लिए रोड के दोनों ओर भूमि चिन्हांकन का कार्य प्रारंभ हो गया है। सर्वे दल द्वारा लगभग मध्य बिंदु से दोनों ओर 30-30 मीटर दूरी तक खंभे लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान कसारबर्डी ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए दल को निशान लगाने से रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि, ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नियमविरुद्ध है। उनका आरोप है कि, पंचायत की बैठक में इस विषय पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, फिर भी प्रशासन ने सीधा कार्य आरंभ कर दिया है। हालाकि चिन्हांकन प्रक्रिया का कार्य बिना रुकावट के किया जा रहा था। आदिवासी संगठन के धर्मेंद्र डामोर ने जब कार्य कर रहे लोगो से अनुमति ओर स्थानीय अधिकारियों की अनुपस्थि को लेकर सवाल दागे जिसके बाद खंभे गाड़ने के कार्य में लगे लोग लौट गए। बताया जा रहा कि, कई ग्रामीणों ने इस विरोध के बाद खेत में लगाए गए खंभे उखाड़ फेंके है। बदनावर-पेटलावद-टिमरवानी मार्ग की 84 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क लगभग 1900 करोड़ रुपये की लागत से बननी है। जिसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सर्वे और चिन्हांकन के बाद स्पष्ट होगा कि, किसकी भूमि, कुएं, नलकूप या अन्य संरचनाएं अधिग्रहण क्षेत्र में आती हैं। यही निशानी आगे मुआवजा निर्धारण का आधार बनेगी। निशान लगने के बाद कई किसानों में चिंता बढ़ी है, क्योंकि कई खेतों की आधी से अधिक भूमि अधिग्रहण की जद में आ रही है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से विरोध के स्वर भी तेज हो रहे हैं। कसारबर्डी क्षेत्र में ग्रामीणों और सर्वे दल के बीच तीखी बहस हुई।

धर्मेंद्र डामोर द्वारा खंभे गाड़ने का किया विरोध।

दल के सदस्यों ने कहा कि, वे सिर्फ अपना निर्धारित कार्य कर रहे हैं,जहां विरोध हुआ, वहां से आगे बढ़ गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि, जब तक ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली जाती, वे अधिग्रहण का विरोध जारी रखेंगे।

पूर्व में कर चुके है विरोध

बदनावर-पेटलावद-टिमरवानी मार्ग में जा रही जमीनों को लेकर किसान सहित आदिवासी संगठनों ने विरोध दर्ज करवाते हुए। स्थानीय ओर जिलाधिकारियों को ज्ञापन तक देकर अपनी मांगे की गई है। आदिवासी संगठनों ने सरकार से आदिवासियों की जमीन लेने पर सवाल उठाया। तो जिन किसानों की जमीन गई उसमें सारंगी, करड़ावद ओर आसपास के किसानों ने भूमि पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर सवाल उठाए है। जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग मुआवजे का प्रावधान को लेकर विरोध दर्ज करवाया।

प्रशासन और पुलिस ने शहर में हादसों का हल प्रतिबंध निकाला, अब व्यापारी परेशान

अदूरदर्शी निर्णय का खामियाजा भुगतने को मजबूर आमजन, व्यापारी और वाहन मालिक

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो कई बार जिला प्रशासन के निर्णय शहर में चर्चा का विषय बनते रहते है। हालांकि इनका उद्देश्य सही और सटीक होता है लेकिन अदुरदर्शिता के कारण प्रशासनिक आदेश या तो हंसी का पात्र बनते दिखाई देते है या फिर आमजन की परेशानी का कारण बन जाते है। मगर विडम्बना यह कि, प्रशासन अपने तुगलकी फरमानों में तब्दीली की कोशिश का उस पर विचार विमर्श करना भी उचित नहीं समझता। आदेश जारी करने के बाद प्रशासन और उसमें बैठे आला अधिकारी यह जानने भर की जहमत भी नहीं उठाते कि, जारी आदेशों के परिणाम सकारात्मक होंगे या नकारात्मक...? प्रशासन और उसमें बैठे आला अधिकारियों की सोच भले ही सकारात्मक हो लेकिन जमीनी हकीकत को जाने बिना वे सरकारी गलियारों से एसे आदेश जारी कर देते है मानों कमान से निकला तीर वापस नहीं लौटेगा। आदेश जारी होने के बाद जब स्थितियां विकट होती और पानी सर से उपर निकल जाता तब जिला मुख्यालय के बासिंदों की नींद खुलती और वे प्रशासन के पास इस गरज से पहुंचते है कि, कमान से निकला तीर वापस हो जाए। लेकिन सरकारी कमान से निकला तीर ना तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता और ना ही वापस हो पाता। नतीजा इस तरह के आदेशों का खामियाजा आमजन को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है।

ऐसा ही एक आदेश 13 अगस्त को जिला प्रशासान की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया। आदेश में शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इस आदेश के पीछे प्रशासन ने जो वजह बताई वह बहुत गंभीर थी। प्रशासन का तर्क यह था कि, पिछले कुछ माहों में शहर में काफी वाहन दुर्घटना हो रही है और इससे आमजन, राहगीरों व स्कूली बच्चों को खतरा बना रहता है। बात भी सही है, लेकिन समस्या का समाधान पूर्णतः प्रतिबंध कैसे हो सकता है...? क्योंकि जिन वाहनों को प्रतिबंधित किया है वे तो शहर के बाहर रूक जाएंगे। लेकिन जिन वाहनों को प्रशासन व कलेक्टर ने अपने आदेशों में छूट दी, अगर उससे किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उसका क्या...? क्या दुर्घटनाएं सिर्फ माल वाहक वाहनों से ही घटती है...? दुर्घटनाएं तो किसी भी वाहन से हो सकती है। मगर सिर्फ माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध लगाना कोई समस्या का समाधान तो नहीं है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद लगभग एक माह बीता और आमजन व व्यापारियों ने यह सोचा कि, अब प्रतिबंध हट जाएगा। लेकिन 19 सितम्बर को कलेक्टर ने अपने 13 अगस्त के आदेश को पुनः रिपीट करते हुए शहर में भारी माल वाहक वाहनों के प्रवेश को पुर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। अब व्यापारियों और आमजन की समस्या यह कि, ट्रंसपोर्ट से आने वाला माल अगर सुबह सात बजे के पहले शहर में नही पहुंचा तो फिर वह माल लगभग 13 घंटे शहर के बाहर ही वाहन में पड़ा रहेगा, जब तक प्रतिबंध की अवधी रात्री 8 बजे समाप्त नहीं हो जाती। अब व्यापारियों की दिक्कत यह है कि, अगर उन्हे दिन में ही अपना माल लाना हो तो उन्हे अपनी जेबें खाली करना पड़ रही है। व्यापारी और आमजन दिन में शहर के बाहर खड़े माल वाहक भारी वाहनों से अपना माल लाने के लिए छोटे वाहन की व्यवस्था करते और वह वाहन शहर के बाहर जाकर बड़े वाहन से माल लेकर शहर में पहुंचाता। इसके लिए व्यापारियों और आमजन को अच्छा-खासा भाड़ा छोटे वाहनों को चुकाना पड़ रहा है। लोडिंग रिक्शा और छोटे वाहन मालिक को इस बात का लाभ जरूर हो रहा है, लेकिन व्यापारियों को अपना ही माल लाने के लिए अपनी जेब से अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ रहा है।

बड़ी विडम्बना यह कि, शहर में बायपास की कमी होने के कारण आलीराजपुर, जोबट, राणापुर से झाबुआ होकर मेघनगर, थांदला, रतलाम तरफ जाने वाले वाहनों को या तो झाबुआ शहर पार करने के लिए कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है या फिर लंबी दूरी के रास्ते तय करना पड़ रहे है। इसी तरह राणापुर से कल्याणपुरा तरफ जाने के लिए भी शहर के बीच से होकर ही गुजरना पड़ता है, जो प्रतिबंधात्मक आदेश के चलते संभव नहीं है। नतीजा माल एक स्थान से दुसरे स्थान पर पहुंचने में घंटों का विलम्ब हो रहा है। जिसका खामियाजा व्यापारियों को ही भुगतना पड़ रहा है। कम से कम प्रशासन को इतनी सूझबूझ तो दिखाना ही चाहिए थी कि, जिस मार्ग पर बायपास की व्यवस्था नहीं है उस मार्ग के वाहनों को शहर से होकर गुजरने की छूट देनी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं हुआ।

पिछले दिनों शहर के व्यापारी इसी समस्या को लेकर एसपी और कलेक्टर से मिले भी थे। उन्होने दोनों ही अधिकारियों को अपनी समस्या के बारे में बताकर नियमों में परिवर्तन करने की मांग की थी, लेकिन व्यापारियों के इस अनुनय-विनय का कोई खास फर्क अधिकारियों को नहीं हुआ। अब तक जिला प्रशासन या किसी अधिकारी का आधिकारिक संशोधन आदेश इस संबंध में जारी नहीं हुआ है। अब आगे त्यौहारिया सीजन है बड़े त्यौहारों की आहट सुनाई दे रही है, इस स्थिति में व्यापारियों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि त्यौहारों के पहले माल का स्टॉक करना भी जरूरी है। ऐसे में व्यापारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिबंध के कारण माल वाहक वाहनों को कई घंटों शहर के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है, जिससे व्यापारियों पर भी खाफी दबाव बना रहता है। माल वाहक वाहनों के चालक भी इस प्रतिबंध की वजह से परेशान होते है कि, गाड़ी खाली होने में उन्हे कई घंटों का बेवजह इंतजार करना पड़ता है। कई बार व्यापारी और माल वाहक वाहन चालकों के बीच इसी बात को लेकर रस्सा कसी तक हो जाती है। हालांकि इसमें ना तो व्यापारी का कोई दोष है और ना ही माल वाहक भारी वाहन चालकों का। यह दोनों ही प्रशासन की अदुरदर्शिता का शिकार हो रहे है। इसके अलावा कई प्रकार की खाद्य सामग्री लेकर शहर में आने वाले भारी वाहन भी इस तरह के आदेश का दंश झेल रहे है। समस्या यह कि अगर समय पर वाहन में रखी खाद्य सामग्री या फ्रुट निकाल कर सही जगह नहीं पहुंचाया तो व्यापारियों का भारी नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है।

अब प्रशाासन के जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों पर सवाल यह उठ रहे है कि, आखिर इस बात का पैमाना क्या है कि, किस वाहन से दुर्घटना होगी और किस वाहन से दुर्घटना नही होगी...? जबकि प्रशासनिक आदेश में कई वाहनों को शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है। जिसमें एमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस, फायर, शासकीय सेवा में लगे हुए वाहन, एमपीईबी के वाहन, दुग्ध संघ के वाहन, तमाम तरह के स्कूली वाहन, तमाम तरह की सवारी बसें, पेट्रोलियम से भरे टेंकर, सरकारी अनाज ढोने वाले वाहन जो वेयर हाउस तक आते-जाते है, खाद वितरण में लगे भारी वाहन जो मेघनगर रेल्वे रेक से जिले भर में खाद या अनाज पहुंचा रहे है, टेउक्टर,लोडिंक भारी मशीने आदि। इस प्रकार के सभी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे है। तो क्या सरकारी आदेश के अनुसार यह मान लिया जाए कि, इन वाहनों से कोई दुर्घटना नहीं होगी और ट्रांसपोर्ट या व्यापारियों का माल लेकर आने वाले वाहनों से ही दुर्घटना होगी...? अगर ऐसा नहीं है तो फिर महज कुछ माल वाहक वाहनों को शहर के बाहर रोकना कहां तक उचित है...? क्योंकि अगर कुछ वाहनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग शहर में हर तरह का वाहन बेधड़क दौड़ता नजर आ रहा है।

प्रशासन व कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश अधिकारियों की अदुरदर्शिता का पैमाना बता रहे है कि, जिले में बैठे अधिकारी किस तरह से माथा उतारनी करते है। ऐसा नहीं है कि, इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंध ही है। इसके लिए और भी उपाय किए जा सकते है। उदाहरण के लिए जिस मार्ग पर बायपास की व्यवस्था नहीं है उस मार्ग पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त स्पीड ब्रेकर लगाए जा सकते थे, शहर के छोर पर बने चौराहों पर ट्राफिक लाइट की व्यवस्था कर यातायात को नियंत्रित किया जा सकता था। इसके अलावा यातायात अमले की सहायता से भारी वाहनों की गति को नियंत्रित किया जा सकता था। मगर इन सबके इतर प्रशासन व कलेक्टर का शहर में सिर्फ भारी माल वाहक वाहनों का प्रतिबंधात्मक आदेश तुगलकी फरमान साबित होता नजर आ रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422